राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 343 , पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार , 23 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की विस्तार की अटकलों के बीच लगातार केंद्रीय नेतृत्व की बैठकें चल रही है। अब इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने वाली है। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच यह बैठक हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। नड्डा पिछले एक महीने से पीएम आवास से सतत संपर्क में हैं।

महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर 30 तक रोक बढ़ी

ग्वालियर, (प्रसं)। कोरोना संक्रमण मद्देनजर परिवहन सेवाओं को संचालित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब परिवहन आयुक्त के निर्देश पर अपर परिवहन आयुक्त ने एक बार फिर आदेश जारी कर महाराष्ट्र से आने एवं जाने वाली बस सेवाओं को 30 जून तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। संक्रमण के चलते पहले भी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन जून माह में जब प्रदेश सहित अन्य प्रदेश में कोरोना का असर कम हुआ तो कुछ राज्यों से आने एवं जाने के लिए बसों की संचालन शुरू कर दिया गया था।

नमाज अदा कर लौट रहे इंस्पेक्टर परवेज शहीद

जम्मू, (एजेंसी)। आतंकवादियों ने मंगलवार रात को कश्मीर के नौगाम स्थित मस्जिद के बाहर हमला कर दिया। इसमें सीआइडी इंस्पेक्टर परवेज डार की मौत हो गई। इस हमले के उपरांत आतंकवादी घटनास्थल से फरार हो गए। सुरक्षाबलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया है। जानकारी के अनुसार, पारिमपोरा पुलिस स्टेशन में तैनात सीआइडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नौगाम स्थित कनीपोरा मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर लौट रहे थे तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया।

उपभोक्ता संरक्षण नियम में होगा संशोधन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और नियामक व्यवस्था को और मजबूत करना है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन को लेकर 15 दिनों के भीतर (6 जुलाई, 2021 तक) सुझाव मांगे गए हैं। ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से केंद्र ने 23 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित किया था।

उच्च हिमालयी क्षेत्र में फंसे 22 लोगों का एयर रेस्क्यू

नैनीताल, (एजेंसी)। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से चीन सीमा से सटे उच्च हिमालयी गांवों में जीवन कितना दुष्कर हो गया है, इसकी बानगी मंगलवार को देखने को मिली। शासन और प्रशासन की सक्रियता के चलते छह बीमारों के साथ ही कुल 22 लोगों को हेली सेवा से धारचूला लाया गया। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। जिससे पुल एवं सड़कें तथा संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूस्खलन से कौशल विकास का प्रशिक्षण देने गई विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मियों की एक 20 सदस्यीय टीम दुगतू एवं ढांकर गांव में फंस गई थी।

देश में 22 केस मिलने के बाद डेल्टा+ को केंद्र ने घोषित किया वैरिएंट ऑफ कंसर्ट

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में खतरा ज्यादा, अलर्ट जारी

नई दिल्ली ■ एजेंसी

कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वैरिएंट को केंद्र सरकार ने वैरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। डेल्टा प्लस वैरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर के लिए खतरा माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में डेल्टा प्लस वैरिएंट के अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं।

भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वैरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। डेल्टा प्लस उसी वैरिएंट का नया रूप है। जब डेल्टा वैरिएंट से इतनी तबाही मच चुकी है तो डेल्टा प्लस तो उसका ही नया रूप है। एक्सपर्ट भी चिंता जता चुके हैं कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आई तो इसके लिए डेल्टा प्लस वैरिएंट जिम्मेदार होगा।

बेहद संक्रामक है डेल्टा प्लस वैरिएंट: एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीवी इंटरव्यू में डेल्टा प्लस को वैरिएंट बेहद संक्रामक बताया है। उनका कहना है कि ये इतना संक्रामक है कि अगर आप इस वैरिएंट से संक्रमित किसी कोरोना मरीज के बगल से बगैर मास्क के गुजरते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। उनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि अब इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि वैक्सीन इस वैरिएंट के खिलाफ असरदार है या नहीं। डॉ. गुलेरिया का कहना है कि भारत में अभी इस वैरिएंट का प्रसार सीमित है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस समेत दूसरे वैरिएंट के मद्देनजर अगले छह से आठ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड असरदार है और वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में डेल्टा प्लस वैरिएंट के अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं। मंत्रालय ने इसे लेकर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को पत्र भी लिखा है। सतर्क रहना बेहद जरूरी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 16 मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव व केरल और शेष छह मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों एवं केरल में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि डेल्टा वैरिएंट 80 देशों में और डेल्टा प्लस वैरिएंट भारत के अलावा नौ देशों में है। अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, रूस और जापान में भी डेल्टा प्लस वैरिएंट मिले हैं। वहीं, केरल राज्य में मंगलवार तक में डेल्टा प्लस वैरिएंट के तीन मरीज मिल चुके हैं।

क्या है डेल्टा प्लस वैरिएंट

यह डेल्टा वैरिएंट के रूप में हुए बदलावों की वजह से डेल्टा प्लस वैरिएंट बना है। डेल्टा वैरिएंट यानी बी.1.617.2 जो कि पहले भारत में मिला था। फिर बाद के महीनों में यह दूसरे कई देशों में भी पाया गया। कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट में इसके स्पाइक प्रोटीन में 417 बदलाव हुआ है। डेल्टा प्लस वैरिएंट को पहले बी.1.617.2.1 कहा जाता था। यह सबसे पहली बार यूरोप में मिला था। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का जरूरी हिस्सा है। इसकी वजह से ही वायरस मानव शरीर में घुसकर इंफेक्शन करता है।

योग दिवस पर रिकॉर्ड 88.09 लाख खुराकें लगाई गईं

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में लोगों को योग दिवस यानी 21 जून को रिकॉर्ड 88.09 लाख खुराकें लगाई गई। वहीं मंगलवार को 53.40 लाख वैक्सीन के डोज लगाए गए। मंगलवार को सबसे ज्यादा 7.96 लाख डोज उत्तर प्रदेश में दिए गए। हालांकि, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा मध्य प्रदेश का है। मप्र ने सोमवार को 16.95 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। कोविन.गॉव.इन पर दिए डेटा के मुताबिक, मंगलवार को यहां सिर्फ 4,825 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।

77.8 फीसदी असरदार है कोवैक्सीन: वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की समीक्षा बैठक के आंकड़े सामने आ गए हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन 77.8 फीसदी असरदार है।

तीसरी कोविड लहर हमारे हाथ में है, वैक्सीन ही समाधान

नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर को विफल करना लोगों के हाथ में है, क्योंकि अगर कोविड के उचित व्यवहार का पालन और और अधिकांश लोग टीका लगवाते हैं, तो इसे रोका जा सकता है। ऐसे कई देश हैं जहां दूसरी लहर भी नहीं आई है।

शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं का ढाई घंटे मंथन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस को किनारे कर विपक्ष के अन्य दलों को नए मंच पर लाने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार के दिल्ली आवास पर मंगलवार को विभिन्न दल के नेताओं की बैठक ढाई घंटे बाद समाप्त हो गई है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाले यूपीए की जगह अब एक नए गठबंधन की कवायद तेज हो गई है। बैठक को लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा की ओर से आई। हालांकि उन्होंने बस इतना ही कहा कि राष्ट्र मंच की बैठक ढाई घंटे चली और कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

तीसरे मोर्चे की कवायद तेज

पवार ने नहीं बुलाई बैठक: राकांपा नेता मजीद मेमन ने कहा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि राष्ट्र मंच की यह बैठक शरद पवार ने भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए की थी। यह पूरी तरह गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बैठक पवार के आवास पर हुई लेकिन उन्होंने यह बैठक नहीं बुलाई। मेमन ने यह भी कहा कि यह बैठक राष्ट्र मंच के प्रमुख यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी।

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की गरिमा से समझौता नहीं

गुप्कर समूह ने घोषणा की कि उसके वे सभी नेता गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगे, जिन्हें केंद्र ने आमंत्रण दिया है लेकिन जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा।

- जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोग के डिप्टी कमिश्नर चंद्र भूषण बुधवार को सभी 20 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत भाजपा विधायकों के साथ बैठक के दौरान।

राहुल गांधी ने जारी किया श्वेत पत्र

श्वेत पत्र में हैं तीसरी लहर का असर नियंत्रित करने के सुझाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड ने गहरा दर्द दिया है और इसके कारण देश ने लाखों लोगों को खोया है, लेकिन सरकार अभी भी संभल नहीं रही है इसलिए पार्टी ने श्वेत पत्र जारी कर सरकार को संभावित तीसरी लहर का असर नियंत्रित करने के सुझाव दिए हैं।

श्री गांधी ने मंगलवार को विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी ने यह श्वेत पत्र विस्तृत रूप से तैयार किया है। उनका कहना है कि इस श्वेत पत्र के ज़रिए उनका मक़सद सरकार पर अंगुली उठाना नहीं बल्कि सरकार ने पहली और दूसरी लहर को मात देने के दौरान जो गलतियां की है, संभावित तीसरी लहर में उन गलतियों को सुधारने और सही कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को ठीक करना होगा। पूरा देश जानता है कि दूसरी लहर से पहले हमारे वैज्ञानिकों और डाक्टरों ने दूसरी लहर आने की बात की थी।

श्वेत पत्र के चार अहम बिंदु

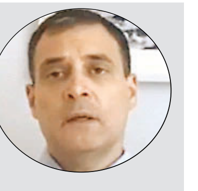

- तीसरी लहर की तैयारी करे सरकार
- कोविड मुआवजा कोष बनाया जाए
- गरीबों छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाए
- पहली और दूसरी लहर की गलतियों के कारणों का पता लगा जाए

राहुल कोविड संकट को लेकर राजनीति कर रहे हैं

भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कोरोना वायरस संकट को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। गांधी द्वारा इस पत्र को जारी करने के कुछ घंटों बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सोमवार से हमें इस बात की आशंका थी। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी इसे पटरी से उतारने के लिए कुछ करते हैं।

हजार लोगों के धर्मातरण का मामला

उमर, जहांगीर सात दिन के एटीएस रिमांड पर

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में हजार से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराने वाले दोनों आरोपितों की रिमांड उत्तर प्रदेश एटीएस को मिल गई है। उप्र एटीएस ने सोमवार को मोहम्मद उमर गौतम तथा मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को लखनऊ से गिरफ्तार किया था।

उप्र एटीएस को मंगलवार को गरीब महिलाओं के साथ मूक-मधिर गरीब बच्चों तथा अन्य हजार से अधिक लोगों का मतांतरण कराने के आरोपित मोहम्मद उमर गौतम तथा मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी की सात दिन की रिमांड मिल गई है। उप्र एटीएस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया था जिसमें अन्य धर्मों से संबंधित काफी गरीब व्यक्तियों और बच्चों के बोलने और सुनने की अक्षमता वाले बच्चों का इस्लाम में अवैध मतांतरण कराया जाता था। उमर गौतम तथा जहांगीर कासमी को उत्तर प्रदेश एटीएस ने सोमवार को एसीजेएम सत्यवीर सिंह की कोर्ट में पेश किया गया था।

राज्यों को अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति देंगे

हमने जरूरत के हिसाब से आर्थिक उपाय किए: मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से आर्थिक उपाय तय किए। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन के मामले में 'सभी के लिए एक जैसा' पैमाना नहीं अपनाया जा सकता।

केंद्र-राज्य भागीदारी में पूरे विश्वास के साथ और प्रोत्साहन के जरिये हमने इन सुधारों को आगे बढ़ाया है। सोशल मीडिया मंच लिंक्डइन पर पोस्ट में मोदी ने कहा कि दुनियाभर में वित्तीय संकट के बीच भारत के राज्य 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से अधिक ऋण जुटाने में सफल हो सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2020-21 में राज्यों ने 1.06 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज जुटाया। केंद्र-राज्य भागीदारी के जरिये इताना अतिरिक्त संसाधन जुटाना संभव हो सका। कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया की सरकारों के समक्ष नीति-निर्माण की दृष्टि से चुनौतियों के रूप में आई है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत कोई अपवाद नहीं है। जन कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के साथ (वित्तीय) स्थिरता को सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब हमने कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन तैयार किए, तो यह सुनिश्चित किया कि सभी क्षेत्रों को एक ही तराजू पर न तौला जाए। एक संघीय व्यवस्था वाले देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नीतिगत उपाय करना जिसके जरिये राज्य सरकारों सुधारों को आगे बढ़ा सकें, काफी चुनौतीपूर्ण है।

पीएम मोदी की बैठक में शामिल होगा गुपकार अलायंस, कहा-अनुच्छेद 370, 35-ए पर कोई समझौता नहीं होगा

श्रीनगर । तमाम अटकलों के बीच मंगलवार को पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पीएजीडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर 24 जून को होनी वाली बैठक में शामिल होने का एलान कर दिया है। पीएजीडी ने वार्ता के लिए अपना एजेंडा भी स्पष्ट करते हुए कहा कि वे जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए पांच अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति की बहाली पर जोर देगा।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीएजीडी नेताओं ने बताया कि डॉ फारूक अब्दुल्ला के साथ महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारीगामी 24 जून को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगे। पीएजीडी नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉ अब्दुल्ला ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निमंत्रण मिला है। हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने अपना रुख रखेंगे।

उन्होंने कहा कि जब बैठक खत्म होगी तो हम आपको बताएंगे कि वहां क्या किया। हमने क्या कहा और क्या प्रतिक्रिया हुई। पीएजीडी जम्मू और कश्मीर में छह पार्टियों का एक गठबंधन है, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दल नेकां और पीडीपी भी शामिल हैं। यह गठबंधन केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद गठित किया गया था।

पीएम मोदी की बैठक में पीएजीडी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस पर डॉ फारूक ने कहा कि वह खुद, महबूबा मुफ्ती और एमवाई तारीगामी बैठक में शामिल होंगे। पीएजीडी के प्रवक्ता तारीगामी ने कहा कि लोगों में यह गलत धारणा नहीं जानी चाहिए कि हम केंद्र सरकार के निर्धारित एजेंडे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि प्रस्ताव क्या है। अगर यह लोगों के हित में है तो हम हां कहेंगे और अगर प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित में नहीं हुआ तो उसे मंजूर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।पीएजीडी के सदस्य मुजफ्फर शाह ने यह भी घोषणा की कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को नई दिल्ली सरकार ने जम्मू-कश्मीर के जिन अधिकारों को समाप्त किया है, उसकी पुनर्बहाली पर जोर दिया जाएगा।

सीमा सुरक्षा — चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने बताया, चीन सेना में बदलाव करने में जुटा

पूर्वी लद्दाख में चीन से ज्यादा मजबूत है भारत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलओसी) पर भारत चीन के मुकाबले अधिक मजबूत स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले साल गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन को उसकी कमजोरियों के बारे में पता चला है और उसके बाद से वह अपनी सेना में बदलाव करने में जुटा है।

यह पूछे जाने पर कि सेना के लिए नॉर्दन फ्रंट प्राथमिकता है या वेस्टर्न? रावत ने कहा कि दोनों ही बराबर हैं। एक इंटरव्यू में विपिन रावत ने एलएसी के आसपास पीएलए की गतिविधियों को लेकर कहा, भारत के साथ सीमा पर चीनी तैनाती में बदलाव आ रहा है, खासकर गलवान और दूसरे इलाकों में मई और जून 2020 में जो हुआ। इसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें अधिक प्रशिक्षण और बेहतर तैयारी की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि उनके सैनिक मुख्यतौर पर सिविलियन्स से आते हैं, उन्हें कम अवधि के लिए जोड़ा जाता है। इस तरह के इलाकों में लड़ने और ऑपरेशन के लिए उनके पास अधिक अनुभव नहीं होता है। यह एक मुश्किल और पहाड़ी क्षेत्र है। आपको इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसमें हमारे सैनिक अधिक दक्ष हैं, क्योंकि पहाड़ों पर युद्ध की हमारी ट्रेनिंग अधिक है।

कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, भटके हुए युवाओं को समझाने की जरूरत

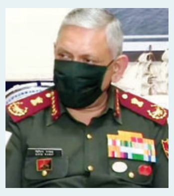

जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सीमा पर अब तक संघर्ष विराम जारी है, जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन ड्रोन का उपयोग करके हथियारों और गोला-बारूद के जरिए घुसपैठ की जा रही है जो कि शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि आंतरिक शांति प्रक्रिया बाधित होती है, तो हम वास्तव में यह नहीं कह सकते कि युद्धविराम अब तक जारी है। युद्धविराम का मतलब यह नहीं है कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें और भीतरी इलाकों में घुसपैठ करें। उन्होंने कहा कि हम पूरे जम्मू-कश्मीर में शांति चाहते हैं। रावत ने कहा कि मुझे पता है कि जम्मू-कश्मीर के लोग खुद शांति स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे आतंकवाद और उग्रवाद देखे हैं।

नई दिल्ली में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर एक बैठक के बाद राष्ट्रीय मंच के अन्य नेताओं के साथ टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा।

न्यूजीलैंड के दवा नियामक ने 12-15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी मंजूरी

क्राइस्टचर्च, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के दवा नियामक मेडसेफ ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को तात्कालिक रूप से मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न को इस वैक्सीन को अगले सप्ताह कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद न्यूजीलैंड में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी।

यह सच है कि बच्चों को गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित होने या मृत्यु होने का जोखिम वृद्ध लोगों की तुलना में कम होता है, फिर उन्हें दो वजहों से टीका लगाना आवश्यक है। पहला कारण यह है कि बच्चे के माध्यम से वायरस अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इनमें उच्च जोखिम वाले समूह के ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें चिकित्सा कारणों से टीका नहीं लगाया जा सकता। कई देशों ने देखा गया है कि कम उम्र के लोगों में इस बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ और यह बड़ी उम्र के लोगों में फैल गया, इससे अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु तक की नौबत आ गई। दूसरी वजह यह है कि बच्चों में बीमारी से मौत का जोखिम भले ही बहुत कम होता है, लेकिन उन्हें कोरोना से संक्रमित होने के फलस्वरूप दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

मेडसेफ द्वारा बच्चों में टीकाकरण का अनुमोदन ठोस आंकड़ों पर आधारित है, जो दर्शाता है कि टीका इस आयु वर्ग के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। इसके पहले यूरोप, अमेरिका और कनाडा ने भी यही किया है। किशोरों का टीकाकरण करने से उनके बीमार होने और दूसरों में वायरस फैलाने का खतरा कम हो जाता है। टीका लगवाकर हम न केवल अपनी, बल्कि अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में, 265,000 बच्चे 12-15 आयु वर्ग में हैं, जो कुल जनसंख्या के 5 फीसदी से अधिक हैं। इसे उन 80 फीसदी में जोड़ें, जो 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो इसका यह मतलब है कि फाइजर वैक्सीन को अब 85 फीसदी आबादी में उपयोग के लिए मेडसेफ की मंजूरी मिल गई है।

यह अच्छी खबर है क्योंकि हर्ड एम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण करने की आवश्यकता है। टीका अनिवार्य नहीं है और यह भी संभावना है कि हर कोई इसे नहीं लेना चाहेगा। इसका मतलब है कि हमें कम उम्र के कुछ बच्चों को टीका लगाने की आवश्यकता हो सकती है। छह से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीका उपयुक्त है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक एशले ब्लूमफील्ड ने कहा कि परीक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर मेडसेफ इन पर विचार करेगा।

कनाडा के दो रोमन कैथोलिक गिरजाघर जलकर खाक

ऑलिवर, (एजेंसी)। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में दो रोमन कैथोलिक गिरजाघर जलकर खाक हो गए। रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस ने बताया कि गश्त पर निकले अधिकारियों ने पेंटिक्टन इंडियन बैंड रिजर्व के सेक्रेड हार्ट चर्च से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। अधिकारियों के घटनास्थल तक पहुंचने तक पूरे गिरजाघर में आग फैल गई थी। इसके दो घंटे से भी कम समय बाद ब्रिटिश कोलंबिया के ऑलिवर में आरसीएमपी को सेंट जॉर्जी चर्च में आग लगने की सूचना मिली। यह गिरजाघर ओसोयूस इंडियन बैंड रिजर्व में स्थित है। आरसीएमपी ने बताया कि दोनों गिरजाघर जलकर खाक हो गए हैं और जांचकर्ता मामले की जांच कर रहे हैं। आरसीएमपी हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच करेगा। सभी तथ्यों तथा सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

सियोल में उत्तर कोरिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि सुंग किम और दक्षिण कोरियाई एकीकरण मंत्री ली इन-यंग ने बैठक की।

वुड्रिज में चक्रवात के बाद बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है।

गोलीबारी में पुलिस अधिकारी व संदिग्ध सहित तीन लोगों की मौत

न्यूयार्क। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के डेनवर उपनगर के अरवाडा में एक बंदूकधारी ने पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। पुलिस की गोली लगने से संदिग्ध की भी मौत हो गई और घायल व्यक्ति ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस उप प्रमुख एड ब्रैडी ने बताया कि सोमवार दोपहर एक बजकर 15 मिनट पर अधिकारी को सूचना मिली थी, शहर में लाइब्रेरी के पास संदेहास्पद घटना का अंदेशा जताया गया था। इसके करीब 15 मिनट बाद पुलिस को गोली चलने और एक अधिकारी को गोली लगने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध की गोली से घायल हुए अन्य व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमलावर भी पुलिस की गोली लगने से मारा गया है। अधिकारियों ने घटना का तत्काल ब्यौरा नहीं दिया और अभी किसी की पहचान उजागर नहीं की गई है। इससे पहले पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों के होने की बात कही थी। घटना शहर के व्यस्त इलाके ओल्ड टाउन अरवाडा में हुई जहां दुकानें, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान हैं। यह स्थान ऐतिहासिक स्थानों की राष्ट्रीय सूची में भी दर्ज है।

ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण अभियान में एक बड़ी बाधा मीडिया भी

क्वींसलैंड, (एजेंसी)। कोरोना वैक्सीन आपूर्ति और इसके प्रबंधन से जुड़े मुद्दों के अलावा, वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट भी ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण अभियान में एक बड़ी बाधा रही है। ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (एटीएजीआई) ने रक्त के थक्के जमने के एक दुर्लभ विकार के चलते अब 60 साल से कम उम्र के सभी लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका की बजाय फाइजर की सिफारिश की है, जो वैक्सीन लगवाने का मन बना रहे लोगों के लिए एक और झटका साबित हो रहा है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में कोविड के सक्रिय मामलों को देखते हुए, अब उन सभी संभावित कारकों पर विचार करने का समय आ गया है, जो वैक्सीन हिचकिचाहट में योगदान दे सकते हैं। इनमें से एक है मीडिया भी है।

हालांकि वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट की खबरें वास्तविक सामुदायिक चिंताओं का वर्णन कर सकती हैं, लेकिन वे अनजाने में ही कोविड वैक्सीन के प्रति एक भय को भी हवा दे सकती हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियाई कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए अनिच्छुक क्यों हैं एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि उनका पर्यावरण सुरक्षित है और कोविड-19 से अपेक्षाकृत मुक्त है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के इच्छुक नहीं हैं। वे टीकाकरण से हिचक रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि टीका अपने आप में वायरस से अधिक जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि बीमारी के डर से लोग टीकाकरण के लिए प्रेरित हुए।

2020 के मध्य में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया था कि यदि उस समय वैक्सीन उपलब्ध होती तब 68 प्रतिशत लोग कोविड-19 वैक्सीन लेते। यह वह लोग थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें वैक्सीन के साइड इफेक्ट, परीक्षण की गुणवत्ता और टीके के विकास की गति के बारे में चिंता नहीं है। हम कह सकते हैं, कि जब ऑस्ट्रेलिया में बीमारी का सामुदायिक संचरण अधिक था, और वैक्सीन से रक्त के थक्कों जैसी दुर्लभ प्रतिकूल घटनाओं की बात सामने नहीं आई थी, बीमारी से सुरक्षा एक प्रमुख चिंता थी। टीके की हिचकिचाहट पर खबरें देने से समस्या और खराब हो सकती है पिछले कई महीनों से, ऐसा लगता है जैसे हर दूसरे दिन समाचारों में एक नई रिपोर्ट या सर्वेक्षण होता है, जो यह खुलासा करता है कि कितने लोग कोविड वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे हैं।

हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने साथियों में टीकाकरण की इच्छा के बारे में जानने के बाद खुद भी टीका लगवाने का मन बनाया। इसी तरह, यह मान लेना जरूरी है कि अगर टीका लगवाने के प्रति लोगों की हिचकिचाहट को बड़े पैमाने पर मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा, तब और ज्यादा लोग टीका न लगवाने के बारे में सोचने वाले है।

अमेरिकी अदालत में कल होगी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर व्यक्तिगत सुनवाई

वॉशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका की एक संघीय अदालत पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में गुरूवार को व्यक्तिगत सुनवाई करेगी। तहव्वुर राणा की 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में संलिप्तता के कारण भारत ने उसे प्रत्यर्पित किए जाने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि भारत से अधिकारियों का एक दल अदालती कार्यवाही के लिए अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका ने अदालत के समक्ष कई अभिवेदनों में प्रत्यर्पण के प्रमाणन संबंधी अनुरोध के पक्ष में अमेरिका के जवाब के समर्थन में घोषणा की है।

राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल होने के मामले में भारत में वांछित है। अमेरिका का कहना है कि 59 वर्षीय राणा का भारत में प्रत्यर्पण भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुरूप है। अमेरिका सरकार ने दलील दी है कि भारत प्रत्यर्पण के लिए राणा सभी मापदंडों को पूरा करता है। अमेरिका ने कहा कि वह राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रमाणन का अनुरोध करता है। अमेरिका का कहना है कि प्रत्यर्पण अनुरोध में संभावित कारण स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और राणा ने भारत के अनुरोध को खारिज करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। राणा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का दोस्त है।

भारत के अनुरोध पर राणा को मुंबई आतंकवादी हमले में संलिप्तता के आरोप में लॉस एंजिलिस में 10 जून, 2020 को फिर से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गये थे। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। पाकिस्तानी मूल का 60 वर्षीय अमेरिकी नागरिक हेडली 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने में शामिल था। वह मामले में गवाह बन गया था और वर्तमान में हमले में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका में 35 साल जेल की सजा काट रहा है।

कंगाल पाकिस्तान में गरीबी से बुरा हाल

वाशिंगटन, (एजेंसी)। दुनियाभर में फैले कोरोना संकट की वजह से पाकिस्तान के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। कोरोना के दौरान काम करने वाले लोगों की आय में कमी आई है। अनौपचारिक और मजदूर वर्ग में रोजगार की सबसे ज्यादा कमी देखी गई है। इस कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही साथ ही गरीबी भी बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि देश में खाने के लाले पड़ रहे हैं और रोजगार का संकट भी गहराता जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में विश्व बैंक का मानना है कि पाकिस्तान में 40 प्रतिशत घरों में लोगों को खाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मजदूरी करने वालों लोगों पर इसकी सबसे ज्यादा मार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में साल 2020 में 4.4 फीसदी से लेकर 5.4 फीसदी तक गरीबी बढ़ी है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। देश चलाने के लिए इमरान सरकार ने आईएमएफ के अलावा कई देशों से भी कर्ज लिया हुआ है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि निम्न-मध्यम-आय गरीबी दर का उपयोग करते हुए वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि साल 2020-21 में पाकिस्तान में गरीबी का अनुपात 39.3 फीसदी है और 2021-22 में यह 39.2 रह सकता है। जबकि 2022-23 में यही अनुपात 37.9 हो सकता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, 2020-21 में गरीबी 78.4 फीसदी थी और 2021-22 में यह 78.3 फीसदी पर पहुंच जाएगी। साल 2022-23 में यह नीचे आकर 77.5 फीसदी तक हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर साल प्रति व्यक्ति होने वाली वृद्धि औसतन केवल दो प्रतिशत है। यह आंकड़ा दक्षिण एशिया के औसत के आधे से भी कम है।

किम के बाद उसकी बहन ने अमेरिका को सुनाई खरी-खरी

सियोल, (एजेंसी)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने अमेरिका के साथ कूटनीति जल्द बहाल होने की संभावनाओं को खारिज कर कहा है, कि वार्ता को लेकर अमेरिका की उम्मीदें उस और अधिक निराश करेंगी। किम जोंग उन ने हाल में अपने अधिकारियों से कहा था कि वे वार्ता और टकराव दोनों के लिए तैयार रहें। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने किम जोंग उन के इस बयान को दिलचस्प संकेत बताया था। सुलिवन की टिप्पणी के बाद किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने यह बयान दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, किम यो जोंग ने कहा, ऐसा लगता है कि अमेरिका हालात की व्याख्या स्वयं को दिलासा देने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह उम्मीद उस और निराश कर देगी। उनका यह बयान तब आया, जब उत्तर कोरिया मामलों के शीर्ष अमेरिकी दूत सुंग किम दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं।

तालिबान ने एक और महत्वपूर्ण अफगान जिले पर किया कब्जा

काबुल, (एजेंसी)। 11 सितंबर तक अमेरिकी और नाटो के शेष सैनिकों की वापसी से पहले तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के उत्तरी कुंदुज प्रांत के महत्वपूर्ण जिले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और प्रांतीय राजधानी की घेराबंदी कर दी। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में एक मई से अमेरिकी और नाटों सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से कई जिलों पर तालिबान का नियंत्रण हो गया है। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता इनामुद्दीन रहमानी ने बताया कि इमाम साहिब जिले के आसपास लड़ाई रविवार को शुरू हुई और सोमवार को दोपहर तक चली। तालिबान ने जिला मुख्यालय पर हमले किए गए और पुलिस मुख्यालय पर कब्जा जमा लिया। तालिबान के लड़ाके कुंदुज प्रांत की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, लेकिन शहर में नहीं घुसे।

ऐसी कुछ खबरें हैं कि बाहरी इलाके में तालिबान के कुछ लड़ाके मौजूद हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी सरहद पर स्थित उत्तरी कुंदुज के इमाम साहिब की सीमा ताजिकिस्तान के साथ जुड़ी है और यह मध्य एशिया में आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है।

रहमानी ने कहा कि पुलिस और अफगान राष्ट्रीय सेना के सैनिकों ने जिले की हिफाजत का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि शहर की रक्षा के दौरान कितने सुरक्षाकर्मी मारे गए या तालिबान के कितने लड़ाकों की मौत हुई। तालिबान के प्रवक्ता जबिउल्ला मुजाहिद ने पुष्टि की है कि इमाम साहिब जिला अब तालिबान के नियंत्रण में है और हमने सुना है कि कई सैनिकों ने तालिबान के सामने समर्पण कर दिया। कुंदुज में कई और जिलों पर भी आतंकवादी समूह का कब्जा हो गया है। इनमें इमाम साहिब के बगल का अचिन भी शामिल है।

अफगानिस्तान को पुन: आतंकियों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक अमेरिकी और नाटो के शेष सैनिकों की वापसी से पहले बाइडन शुक्रवार को व्हाइट हाउस में गनी से पहली बार आमने-सामने की मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान के अपने समकक्ष अशरफ गनी के साथ बैठक को लेकर उत्साहित हैं। इस दौरान दोनों नेता यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान आतंकवादी समूहों के लिए फिर से पनाहगाह नहीं बने।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने सोमवार को पत्रकारों को बताया, राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में शुक्रवार की बैठक को लेकर उनका (गनी का) स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे उम्मीद है कि बातचीत में यह सुनिश्चित करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवादी समूहों के लिए पनाहगाह नहीं बने। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और सैन्य नेतृत्व अफगानिस्तान में स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। बाइडेन ने पेंटागन को इस साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी का निर्देश दिया है। बाइडन और गनी के बीच यह उच्चस्तरीय बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब तालिबान के लड़ाकों ने हाल के सप्ताह में अफगानिस्तान के कई नए जिलों पर कब्जा कर लिया है और दोनों पक्षों से कई लोगों के हताहत होने की सूचना है।

फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने वेस्ट बैंक शहर नब्लस के दक्षिण में बीता गांव में यहूदी बस्तियों के विस्तार के विरोध में टायर जलाए।

कोरोना के जन्म को लेकर घिरी वुहान लैब

पेइचिंग, (एजेंसी)। कोरोना वायरस के जन्म को लेकर घरिी वुहान लैब को चीन बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शीर्ष वैज्ञानिक पुरस्कार देने जा रहा है। वुहान लैब को ऐसे समय में शीर्ष वैज्ञानिक पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है जब वह कोरोना के लीक होने को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है। वुहान लैब को चाइना एकैडमी ऑफ साइंस की ओर से विज्ञान और तकनीक उपलब्धि पुरस्कार से दिया जाएगा। यही नहीं चीन में बैट वूमेन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक शी झेंगली के काम की भी विशेष तारीफ की गई है। शी झेंगली वुहान लैब में पशुओं पर शोध का नेतृत्व करती हैं। चाइना अकादम ऑफ साइंस ने कहा कि वुहान लैब के शोधकताओं के दल ने कोरोना वायरस महामारी के कारणों की व्यापक और व्यवस्थित तरीके से जांच की। इसके परिणामों के फलस्वरूप कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं और वैक्सीन को बनाने का रास्ता साफ हुआ। साथ ही वुहान लैब ने महामारी के प्रसार को रोकने और बचाव के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन मुहैया कराया।

इधर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह वायरस वुहान लैब से लीक होकर वहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित वुहान वेट मार्केट पहुंच गया। यही पर कोरोना महामारी की सबसे पहले पहचान हुई थी। यही नहीं चीन की वुहान लैब में पिंजरे के अंदर चमगादड़ों को रखा जाता था। वुहान लैब से पहली बार सामने आई तस्वीरों में यह खुलासा हुआ है। वुहान लैब की इन तस्वीरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस दावे खारिज कर दिया है जिसमें उसने कोरोना के वुहान लैब से निकलने के संदेह को षडयंत्र करार दिया था। चाइना अकादमी ऑफ साइंस के मई 2017 के आधिकारिक वीडियो में चमगादड़ों को पिंजड़े में कैद करके रखा दिखाया गया था। इस वीडियो को वुहान लैब में नए बॉयोसेफ्टी लेवल 4 के हिसाब से सुरक्षा शुरू होने पर जारी किया गया था। इसमें हादसा होने की सूरत में सुरक्षा मानकों को लेकर बताया गया था। इसमें लैब के निर्माण को लेकर फ्रांसीसी सरकार के साथ काफी विवाद के बारे में भी बताया गया था। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि वैज्ञानिक चमगादड़ों को कीड़े खिलाते नजर आ रहे हैं। इस 10 मिनट के वीडियो को पूरी तरह से वुहान लैब के निर्माण पर केंद्रित किया गया है। इसमें कई वैज्ञानिकों के साक्षात्कार भी दिखाए गए हैं। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने अपनी कोरोना की उत्पत्ति की जांच रिपोर्ट में यह नहीं बताया था कि वुहान लैब में चमगादड़ों को रखा जाता था। जांच रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही कहा था कि पशुओं को वुहान लैब में रखा जाता था।

दिल्ली सरकार द्वारा 50% बैठने की जगह के साथ बार को फिर से खोलने की अनुमति के बाद नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में मास्क पहने हुए एक स्टाफ सदस्य, लोकल बार और रेस्तरां में काम करते हुए।

केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया वैश्विक वैक्सीनेशन अभियान एक मजाक है : आतिशी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया वैश्विक वैक्सीनेशन अभियान एक मजाक है। पर्याप्त वैक्सीन के बिना वैश्विक अभियान कैसे शुरू कर सकते हैं यह दुख और आश्चर्य की बात है कि आज से शुरू हो रहे वैश्विक अभियान के बावजूद दिल्ली को वैक्सीन की एक भी अतिरिक्त डोज नहीं मिली। केंद्र सरकार ने जब वैक्सीन का विकेंद्रीकरण कर राज्यों को वैक्सीन खरीदने के लिए कहा था तब भी अभियान विफल रहा था क्योंकि राज्यों को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया गया और जब अभियान को केंद्रीकृत कर दिया है तब भी विफल है। केंद्र सरकार का वैश्विक वैक्सीनेशन अभियान केवल विज्ञापनों और घोषणाओं तक सीमित है। वास्तविकता यह है कि दिल्ली को आज एक भी वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से दिल्ली को जुलाई में केवल 15.19 लाख वैक्सीन की डोज मिलेंगी। इस रफ्तार से पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने में 13 महीने से भी ज्यादा समय लगेगा। केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान का कुप्रबंधन और गलत योजना बनायी गई। हमें नई नीतियां मिलती रहती हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। केंद्र सरकार ने अभी तक फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन आदि डब्ल्यूएचओ द्वारा मंजूर वैक्सीन को अनुमति नहीं दी है, लेकिन सामूहिक वैक्सीनेशन के बारे में बात करते रहते हैं। क्या यह उनके द्वारा किया जा रहा मजाक है विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 8.25 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं। ऐसे में 5 दिन का कोवैक्सीन और 57 दिन का कोवीशील्ड का स्टॉक उपलब्ध है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 2.68 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिसमें कोवैक्सीन का 1 दिन का और कोवीशील्ड का 13 दिन का स्टॉक उपलब्ध है।

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार देश के हर उस व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी जो कि वैक्सीन लगवाने के योग्य है। ऐसे में दिल्ली सरकार की उम्मीद थी कि 21 जून को केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की काफी सारी डोज उपलब्ध कराई जाएंगी। जिससे कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लिए हो रही वैक्सीन की किल्लत खत्म होगी और दिल्ली की पूर्ण आबादी का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होगा। हमें इस बात का दुख और आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार को 21 जून के दिन एक भी अतिरिक्त वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। यह कैसा टीकाकरण का अभियान है जहां सिर्फ घोषणा और विज्ञापन है, लेकिन वैक्सीनेशन कहीं पर भी नहीं है।

विधायक आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को ईमेल आया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं का भी वॉक इन वैक्सीनेशन होना चाहिए। दिल्ली सरकार भी वॉक इन वैक्सीनेशन जरूर करेगी लेकिन जब तक वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मुहैया नहीं करायी जाएंगी तब तक इस वैक्सीनेशन अभियान का क्या मतलब है। केंद्र सरकार की तरफ से कि दिल्ली को अगले माह 1 जुलाई से कुल 15.19 लाख वैक्सीन की मिलेंगी। पिछले कई महीनों से मिल रहीं डोज से यह कम ही है। दिल्ली सरकार को 18 से 44 वर्ष की श्रेणी और 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए जून में 14 लाख, मई में 13.25 लाख और अप्रैल में 23 लाख वैक्सीन की डोज मिली थीं। जब केंद्र सरकार यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान नहीं चला रही थी तब दिल्ली को 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए अप्रैल में 23 लाख वैक्सीन की डोज दी थीं। अब जब तथाकथित रूप में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, तब सिर्फ 15 लाख वैक्सीन की डोज दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की अभी तक 65,26,770 डोज लग चुकी हैं, जिसमें से 15,78,382 लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। दिल्ली में अभी भी 83.73 लाख ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। इन 83.73 लाख लोगों को वैक्सीन की दो डोज लगनी है तो 1.6 7 करोड़ वैक्सीन की डोज की आवश्यकता है। दिल्ली में 33 लाख ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की एक डोज लगी है, जिनको अभी वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है। अगर दोनों आंकड़ों को जोड़ें तो यह निकल कर आता है कि दिल्ली को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के लिए 2 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहियें। लेकिन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी दिल्ली को जुलाई में सिर्फ 15.1 9 लाख ही वैक्सीन की डोज मिल रही हैं। अगर हम इसी स्पीड पर वैक्सीन की डोज मिलती रहीं तो पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने में 13 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 13 महीने में कोविड की कितनी लहर आ सकती हैं। यह दिल्ली के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। विधायक आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार से अपील है सिर्फ नाम का कार्यक्रम मत चलाइए। आपने कुछ महीने पहले कहा था कि हम वैक्सीनेशन खरीद का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं ताकि राज्य खुद वैक्सीन खरीद सकें। लेकिन जब राज्य वैक्सीन खरीदने गए तो आपने कंपनियों के पीछे से हाथ बांध दिए और कहा कि आप उतनी ही वैक्सीन बेचोगे के जितना कि हम बताएंगे। ऐसे में विकेंद्रीकरण करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज आपने कहा कि 21 जून से हम एक केंद्रीकृत अभियान चलाएंगे, जहां पर केंद्र सरकार सभी को वैक्सीन देगी। 21 जून से वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू हो गया लेकिन दिल्ली को एक भी वैक्सीन नहीं मिली। केंद्र सरकार का वैक्सीनेशन को लेकर कैसी गलत योजना और कुप्रबंधन है कि कभी हम एक नीति लेकर आते हैं और कभी हम दूसरी नीति लेकर आते हैं। देश में नीतियां बदलती रहती हैं लेकिन दिल्ली के पास वैक्सीनेशन नहीं आती है।

यात्रियों के लिए अच्छी खबर, चलेंगी कई और स्पेशल ट्रेनें

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत तमाम राज्यों द्वारालॉकडाउन में ढील देने के साथ ही भारतीय रेलवे ने भी अपने यात्रियों का सफर आसान करने की तैयारी तेज कर दी है। रेलवे ने 25 जोड़ी स्पेशन ट्रेनें शुरू करने की घोषणा करने के साथ इनके शुरू होने की तारीखों का भी एलान कर दिया है। इनमें कई ट्रेनों ने तो सोमवार से ही रफ्तार भरनी शुरू कर दी हैं। इनमें डेढ़ दर्जन ट्रेनें तो दिल्ली से विभिन्न राज्यों के लिए रवाना होंगी। उधर, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर उत्तर रेलवे में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग शिक्षक ने ऑनलाइन रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों को योग का महत्व बताया और इसका अभ्यास कराया।

सुशील अंसल ने पासपोर्ट नवीनीकरण में फर्जीवाड़ा किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि 59 लोगों की जान लेने वाले 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी ठहराए गए सुशील अंसल ने अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए फर्जीवाड़ा किया और अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की अदालत में दायर आठ पृष्ठों के आरोपपत्र में पुलिस ने दावा किया है कि अंसल ने शपथपत्र में यह कहकर सरकारी अधिकारियों को गुमराह किया कि उसे किसी भी अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। अंसल को 2013 में तत्काल आवेदन पर जारी पासपोर्ट के संबंध में पुलिस ने कहा कि यह पाया गया है कि तत्काल पासपोर्ट योजना के तहत दिए गए शपथपत्र में अंसल ने कहा कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और उसे किसी भी अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। पुलिस ने यह आरोपपत्र इस साल फरवरी में दायर किया था, लेकिन लोगों के संज्ञान में यह अब आया है। आरोपपत्र में कहा गया है 2013 में, आरोपी सुशील अंसल ने अपने आवेदन के साथ शपथपत्र दायर किया और उसने शपथ के माध्यम से सरकारी प्राधिकरण (पासपोर्ट कार्यालय) को यह कहकर गुमराह किया कि उसे अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी 2022 को होगी। संबंधित मामला उपहार हादसे के पीड़ितों के संगठन की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर दायर किया गया था। याचिका में कहा गया था कि अंसल ने अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए सूचनाएं छिपाईं या गलत सूचना दी। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।

दो सगी बहनों से हैवानियत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजधानी के दिल्ली कैंट थाना इलाके में कथित तौर पर दो सगी बहनों के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है। रेप के आरोप में दो सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना 19 की है। दोनों पीड़ित बहनों की उम्र 20 और 22 साल के करीब है और वह दिल्ली कैंट इलाके की ही रहने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियों के आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। सीआरपीसी 164 के तहत इन लड़कियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

नई दिल्ली। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बूथ स्तर पर 5 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है।

चार लाख लोगों को राहत देने की तैयारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने की शुरूआत करने के बाद अब दिल्ली में ओ जोन (डूब क्षेत्र) में बसे करीब चार लाख लोगों को भी राहत देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल, मास्टर प्लान-2041 में यमुना के डूब क्षेत्र को दो श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहला क्षेत्र वह होगा जो नदी के बिल्कुल समीप होगा जबकि दूसरी श्रेणी में वह क्षेत्र यमुना से थोड़ा दूर होगा। मास्टर प्लान में यमुना के किनारे 300 मीटर चौड़ा एक बफर जोन बनाने की सिफारिश भी की गई है। संकेत मिल रहे हैं कि 300 मीटर के बफर जोन से बाहर जो भी निर्माण कार्य डूब क्षेत्र में हो रखे हैं, उन्हें कुछ शर्तों के साथ जल्द ही नियमित किया जा सकेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि जनता के सुझाव एवं आपत्तियों के 45 दिन पूरे होने के बाद डीडीए इस बाबत अलग से प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसमें यमुना किनारे बसे इलाकों, गांवों को ओ-जोन से बाहर कर उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। पहले यह प्रस्ताव डीडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा और फिर इसके बाद स्वीकृति के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के छह विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 गांव-कालोनी ऐसे हैं, जिनका बहुत बड़ा इलाका डूब क्षेत्र में बसा हुआ है। कई इलाकों में तो समुदाय भवन, बारात घर समेत कई सरकारी विभागों के कार्यालय भी ओ-जोन में बन चुके हैं। ऐसे में इन इलाकों को नियमित करना आवश्यक बन चुका है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में ओ-जोन के इलाके में बने भवनों-गांवों और कालोनियों के नियमित होने से लगभग चार लाख लोगों को लाभ मिलेगा। खासतौर पर ओखला, बदरपुर, सभापुर, गामड़ी, उस्मानपुर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में ओ-जोन में निर्माण कार्य हो चुके हैं।

पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी के भी बढ़े दाम दिल्ली-एनसीआर के लोगों की बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी जारी है। मंगलवार को एक बार फिर तेल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि वहीं डीजल की कीमत 88.23 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इससे पहले दाम नहीं बढ़ा था। अब एक दिन की राहत के बाद मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 27 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गया है। वहीं, महंगे पेट्रोल-डीजल से त्रस्त दिल्ली-एनसीआर के वाहन चालकों को सीएनजी आधारित वाहन चलाने का सुख भी दूर होता जा रहा है। दिल्ली में सीएनजी का भाव 43.40 रुपये प्रति किलोग्राम है तो एनसीआर में शामिल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में सीएनजी दिल्ली से सात से 16 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हमेशा सीएनजी सस्ती रहती थी। अक्टूबर 2019 में फरीदाबाद में सीएनजी की दर 45.08 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि दिल्ली में 46.60 रुपये प्रति किलोग्राम थी। फिलहाल दिल्ली में सीएनजी की दर कम होने के पीछे टैक्स की कमी बता रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97.22 और डीजल 86.97 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।पिछले एक माह में एनसीआर में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में 10 हजार के लगभग गाड़ियां पेट्रोल सहित सीएनजी पर भी पंजीकृत हुई हैं। सीएनजी की दो तरह की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें ज्यादातर नई गाड़ियां कंपनी से ही सीएनजी की किट लगवाकर ले रहे हैं। वाहन कंपनियों से अलग लगने वाली सीएनजी किट के भाव भी पिछले 6 माह के अंतराल में सात हजार रुपये तक बढ़े हैं।

बसपा की चुप्पी से असमंजस में खेमे के जिला पंचायत सदस्य

गाजियाबाद । जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 14 में से सबसे ज्यादा पांच सीट पाने वाली बसपा उम्मीदवार को लेकर अभी तक चुप्पी साधे है, जिस कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा ने ममता त्यागी तो रालोद-सपा ने नसीम बेगम को दो सप्ताह पहले से उम्मीदवार घोषित कर रखा है।

जानकार कह रहे हैं कि कोई भी संगठन सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारता है। इसके बावजूद प्रत्याशी को तैयारी के लिए समय चाहिए होता है। बसपा के निर्वाचित जिपं सदस्य असमंजस में हैं कि वह चुनाव की तैयारी कर भी लें, लेकिन उम्मीदवारी को लेकर वह आश्वस्त नहीं है।

हालांकि इस बारे में कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। जिपं चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसीलिए सभी दल फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं।

दिल्ली में काबिज आप को पंजाब में दिखाई दे रही उम्मीद की किरण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में लगातार 3 विधानसभा चुनाव में एतिहासिक जीत तर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इनमें सबसे राज्य तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की खास नजर पंजाब पर है। बताया जा रहा है कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में की गई बड़ी भूल से सबक लेते हुए 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं,पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार सिख समाज से ही होगा। अरविंद केजरीवाल से ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा समय आने पर सबको बता दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल समेत आप के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पहले अकाल दल और अब कांग्रेस को आजमाने के बाद बदहाल पंजाब के लोग अब आम आदमी पार्टी को मौका देने की सोच बैठे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आप के विधानसभा चुनाव में उम्दा प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, 20 सीटें जीतकर अकाल दल को छोड़कर विधासभा में मुख्य विपक्षी दल भी बनी। इस बीच बसपा और शिअद के गठबंधन के बाद समीकरणों में बदलाव भी आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि वह न केवल अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बल्कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखलकर आप पंजाब में अगले सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं की मानें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दिवसीय दौरे के दौरान कैडरों को न केवल उत्साहित किया, बल्कि अब तो पार्टीसभी 117 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। राघव चड्ढा (सह-प्रभारी, आम आदमी पार्टी, पंजाब) का कहना है कि पंजाब में सभी सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बार बाहरी नहीं, बल्कि स्थानीय व पंजाबी नेताओं के हाथ में चुनाव की कमान रहेगी। तय रणनीति के हिसाब से उम्मीदवारों व मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी जाएगी।आप ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव-2021 भी लड़ा था और एक तरह से अच्छा प्रदर्शन किया था, खासतौर से सूरत में।आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि गुजरात के लोग भाजपा शासन से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल्ली में हुए आप सरकार के शानदार कामों से गुजरात के लोग बेहद प्रभावित हैं और आम आदमी पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं।

दिल्ली में 11 लाख टीके उपलब्ध, लगे सिर्फ 76 हजार को, भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल

नई दिल्ली । भाजपा ने दिल्ली सरकार पर टीकाकरण अभियान को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सोमवार से केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसे लेकर सभी राज्यों में उत्साह है। पहले दिन देश में 86 लाख लोगों को टीका लगाया गया। अन्य राज्यों में भी इसे लेकर उत्साह है। इसके विपरीत दिल्ली में मात्र 76 हजार लोगों का टीकाकरण हुआ। जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 11 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध थे। मुख्यमंत्री को इसका कारण बताना चाहिए।

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक टीकाकरण पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। अब केंद्र सरकार मुफ्त टीका उपलब्ध करा रही है तो मुख्यमंत्री पंजाब चले गए। इससे पता चलता है कि वह कोरोना से लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं हैं। उनका ध्यान दूसरे राज्यों में राजनीतिक विस्तार पर है। जब उन्हें इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली में होना चाहिए था तो वे पंजाब चले गए। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रमि पंक्ति के कर्मचारी और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने में दिल्ली बहुत पीछे है। जनवरी से मार्च तक दिए गए टीके का सही तरह से प्रयोग नहीं हुआ।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अप्रैल तक 1.82 लाख टीके बराबद हो गए। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों में टीकाकरण केंद्र खोलने की बात कही थी लेकिन मुश्किल से एक हजार केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से टीकाकरण काम का दिल्ली सरकार से लेकर नगर निगमों को दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के टीकाकरण अभियान को विफल करने की साजिश रच रही हैं।

प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली में हो रहे टीकाकरण की आडिट कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि आक्सीजन की तरह टीक की खुराक जमा कर कालाबाजारी करने की साजिश रची जा रही है। जब सभी राज्य टीकाकरण अभियान का उत्सव मना रहे थे। उस समय मनीष सिसोदिया प्रेस वार्ता कर यह भ्रम फैला रहे थे कि केंद्र टीका उपलब्ध नहीं करा रहा है। जबकि यहां 11 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध थे।

संपादकीय

प्रकृति को हारने न दीजिए

यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो वह हमारी रक्षा करेगी। मनुष्य एवं प्रकृति का संबंध अत्यन्त गहरा और चिरकालिक है। मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक अंश है। जिन तत्वों से प्रकृति का जन्म हुआ, वे सभी तत्व मनुष्य के निर्माण में भी सहायक हैं। प्रकृति ने जीव के लिए स्थल, जल, वन और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, जिसे हम 'पर्यावरण' की संज्ञा देते हैं। परंतु आज प्रकृति प्रदत्त जीवनदायी वायु, भूमि और जल प्रदूषण के कारण जीवन घातक बन रहे हैं। प्रकृति को नष्ट करने वालों के बारे में कहा गया है – 'काला धुआं उड़ाने वालों, जल को जहर बनाने वालों। जल्दी सोचो, समझो वरना, सारा खेल बिगड़ जाएगा। प्रकृति उजड़ जाएगी, तो जीवन बहुत पिछड़ जाएगा।' प्रकृति के सान्निध्य में व्यक्ति के भीतर का मौन जागृत हो उठता है। इस मौन को प्राकृतिक नियमों से साधना अत्यंत शांतिदायक होता है। इस अनुभूति से हमारी शिथिल और सामान्य बुद्धि, विवेक, दृष्टि सब जीवन के बारे में उत्कृष्टता से संवर जाती है। जीवधारी चाहे छोटा हो या बड़ा, शांत हो या शोर मचाने वाला, प्रकृति सभी को मिलजुलकर साथ-साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। परंतु अभी चिंता है कि प्रकृति के साथ जुड़कर एक संतोषदायक जीवन की संभावना नहीं बढ़ रही है। मिट्टी के कटाव एवं उसकी उत्पादकता में कमी से भूख एवं पोषण की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है एवं मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को 107 देशों में 94वें स्थान पर दिखाया गया है। भारत को विश्व की एक महाशक्ति बनने के लिए कुपोषण को जड़ से खत्म करना होगा। भावी पीढ़ियों को कुपोषण और उसके चलते बीमारियों से बचाकर ही एक नए भारत के निर्माण की नींव रखी जा सकती है। सबसे जरूरी जल प्रकृति-प्रदत्त अनमोल उपहार है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुरू किए जाने वाले अभियान 'कैच द रेन' को सफल बनाना होगा। इस अभियान का मूलमंत्र है – पानी जब भी जहां भी गिरे, उसे बचाना है। जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल का संचयन करना है एवं उन्हें प्रदूषण से बचाना है। वन भी प्रकृति की अनुपम देन हैं। वन विश्व के लिए वातानुकूलन तथा जमीन के लिए आवरण का काम करते हैं। वे भूमिक्षरण को रोकते है, जल का संचयन करते हैं, हरित गैसों को सोखते हैं, जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान में कमी लाते हैं, सूखा, अकाल, बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति दिलाते हैं। वैदिक मुनियों ने राष्ट्र के सांस्कृतिक, सौन्दर्यमूलक एवं आर्थिक विकास में वनों की भूमिका आवश्यक मानी थी। तमाम धर्मों में वनों के महत्व को स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के लक्ष्य 15 में टिकाऊ वन प्रबंधन पर जोर दिया गया है। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बीमारी, विषमता एवं शोषण से मुक्ति पाने के लिए हमें देश को हरा-भरा बनाना होगा तथा वनवासियों को निराशाओं एवं नकारात्मकताओं से निकालकर आगे बढ़ने का पूरा मौका देना होगा। जैविक संपदा किसी भी राष्ट्र की अनमोल धरोहर होती है। जैव विविधता के मामले में भारत की गणना विश्व के संपन्न राष्ट्रों में की जाती है। फिर भी लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार, वर्ष 1970 से 2016 के बीच लगभग 60 प्रतिशत पशु, पक्षी, जलचर तथा सर्प एवं मछलियों की संख्या में कमी आई है। जानवरों और पौधों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्द्धन द्वारा ही हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर को बचा सकते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है। हमें पर्यावरण के सामने मौजूद चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण ही विविध प्राकृतिक आपदाओं का आगमन हो रहा है। धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए निम्न उपाय अपनाने पड़ेंगे - एक, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, 2050 तक कार्बन-रहित विकास का लक्ष्य अपनाना। दूसरा, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना है, जैसे - सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन इत्यादि। तीसरा, पेड़ों/वनों का संरक्षण करना है, अधिक वृक्षारोपण तथा वनों को आग से बचाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। चौथा, प्लास्टिक, कूड़ा-कचरा का समुचित उपयोग एवं प्रबंधन करना है। आज पर्यावरण की चिंता करते हुए बार-बार ध्यान जा रहा है कि कोविड-19 महामारी ने जीवन तथा जैविकी पर गहरी चोट की है। आशंका है, चमगादड़ जनित यह रोग सारे महाद्वीपों तक पहुंच गया है। अमेरिका, यूरोपीय देशों में भी इसने नाक में दम कर रखा है, जिन्होंने विकसित राष्ट्र होने का तमगा पहन रखा है। इस घड़ी में हमें पर्यावरण संरक्षण के संकल्प एवं संयम, दोनों पर खरा उतरना होगा। कोरोना जल्दी चला जाए तथा निकट भविष्य में दूसरी महामारी न आए, इसके लिए हमें जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रहना है। उनके मांस खाना तथा उन्हें पालतू बनाने की आदत का त्याग जरूरी है। हरित मानसिकता अपनाकर हमें देश को हरा-भरा तथा जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्द्धन का प्रयास करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण लोगों की जीविका से जुड़ा है। पर्यावरण का बिगड़ना गरीबी, भुखमरी, असमानता, बेरोजगारी बढ़ाता है, क्योंकि उनके जीवनयापन का साधन सीधे प्रकृति से जुड़ा है। जमीन बिगड़े, तो किसान मिटा, पानी कम तो मछुआरा मिटा, नदी-तालाब सूखे, तो गांव मिटे। हमें देखना चाहिए कि प्रदूषण ने भी महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर बनाया है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृति के संरक्षण से हमारी ज्यादातर समस्याओं का निदान संभव है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है- प्रकृति नहीं डरकर झुकती/ कभी भाग्य के बल से/ सदा हारती वह मनुष्य के / उद्यम से श्रम जल से। आज सारा विश्व प्रकृति के साथ परस्पर निर्भरता को सुदृढ़ करना चाहता है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में वापस आ गया है। ब्रिटेन जैव विविधता बढ़ाने में सबसे आगे है। भारत इंटरनेशनल सोलर एलायन्स द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन बढ़ाने में विकसित देशों की मदद कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पूरी ताकत से सतत विकास द्वारा विनाशकारी समस्याओं का समाधान निकालने में व्यस्त है। शेक्सपियर ने लिखा था कि 'प्रकृति का हल्का सा स्पर्श, बना देता दुनिया को एक।'

प्रवीण कुमार सिंह

टेक कंपनियां और इनके अरबपति निवेशक अपनीदबंगई से भारत और अन्य देशों को हांकना चाहते हैं

उन्हें लगता है कि जनमानस को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के चलते पूरा विश्वपटल उनके लिए खुला मैदान है। वे बड़े-बड़े नेताओं और चुनी हुई सरकारों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। आधुनिक युग के इन सामंतों में स्टुअर्ट मिल की पेचीदगी, मार्क्स की घातकता और किपलिंग की गोरी श्रेष्ठता कूट-कूटकर भरी है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार अपनी आजादी को इन नव-उपनिवेशवादियों के सामने गिरवी रखने को तैयार नहीं है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिग टेक माध्यम मात्र हैं और उस पर चर्चा नियमित करने का अधिकार सिर्फ भारत की चुनी हुई संसद को है।

यूरोप से उपजा उपनिवेशवाद जिस अहंकार और स्वदेशी संवेदनाओं के दमन में निहित था, उसका पता उपनिवेशवाद को उचित ठहराने वाली समकालीन मानसिकता में मिलता है। अमेरिकी महाद्वीप पर अपने कब्जे को जायज ठहराने के लिए स्पेन ने उस जनादेश का सहारा लिया, जिसके तहत पोप ने गैर ईसाई विश्व पर ईसाई शासकों का नैसर्गिक अधिकार घोषित किया था। मूलतः आर्थिक कारणों से उपजे उपनिवेशवाद को सिर्फ ईसाई रूढ़िवादियों का ही समर्थन प्राप्त नहीं था। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे उदारवादियों ने भी कई प्रकार के तर्क देकर उपनिवेशवाद का बचाव किया था। साम्यवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स तो भारत में अंग्रेजी शासन से इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने इस उपनिवेशवाद के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य भी बता दिए। मार्क्स ने कहा कि ब्रिटिश शासन को एशियाई सामाजिक कल्पना को ध्वस्त कर पाश्चात्य सामाजिक मूल्यों की नींव डालनी चाहिए। यह पश्चिमी विचारधारा के दोनों छोरों पर उपनिवेशवाद की व्यापक जनस्वीकृति का ही लक्षण था कि जंगल बुक के रचयिता और नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग ने अश्वेत लोगों को सभ्यता के दायरे में लाना गोरे लोगों का कर्तव्य बताया। पिछली सदी के छठे दशक तक अधिकांश विश्व को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली, परंतु उसके अवशेष कई माध्यमों से फिर भी बने रहे। संस्कृतियों पर गहरे प्रभाव के अलावा शिक्षा के माध्यम यूरोपीय भाषाओं में बदल गए थे। संस्थागत रूप से भी कहीं कॉमनवेल्थ तो कहीं लैटिन यूनियन जैसे संगठन बने रहे। कई देशों के झंडों और सिक्कों पर आज भी औपनिवेशिक काल के चिन्ह मौजूद हैं। बदली शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा के लिए बहुत से एशियाई और अफ्रीकी लोग पश्चिम का रुख करने पर मजबूर हुए।

बात सिर्फ सांस्कृतिक अतिक्रमण या आर्थिक निर्भरता की नहीं थी।

शोध संस्थाओं, मानवाधिकार संगठनों, राजनीतिक सक्रियता और मीडिया के चतुर उपयोग से वही पश्चिम, जिसने सदियों तक दमन और उत्पीड़न किया, रातोंरात वैश्विक नैतिकता का रखवाला भी बन गया। स्वयं जूलियन असांजे और एड्वर्ड स्नोडन के पीछे पड़ा अमेरिका दूसरे देशों में पत्रकारिता पर खतरे की चिंता प्रकट करता है।

बिग टेक कंपनियां जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, वाट्सएप और इनके अरबपति निवेशक उस फेहरिस्त में जुड़ गए हैं, जो अपनी दबंगई से भारत और अन्य देशों को हांकना चाहते हैं। जहां पूर्वाग्रहग्रस्त पश्चिमी मीडिया पत्रकारिता के अधिकारों की दुहाई देता है, वहीं तकनीकी कंपनियों ने निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना हथियार बनाया है। जिस निजता के अधिकार की दुहाई देकर आज तकनीकी कंपनियां भारत सरकार से टकराव की स्थिति में हैं, उसी निजता की अवहेलना कर फेसबुक ने कैंब्रिज एनालिटिका को लाखों भारतीयों का डाटा बेच दिया था। जो तकनीकी कंपनियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की माला जपते नहीं थकतीं, उनके अपने दफ्तरों में भी स्थिति एकदम भिन्न है। 2018 में करीब 100 फेसबुक कर्मियों ने कंपनी में वाम-उदारवादियों की घोर असहिष्णुता के खिलाफ मोर्चा खोला था।

ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने खुद माना था कि उनके संगठन में वामपंथी झुकाव है और उनके गैर वामपंथी सहकर्मी अपनी राजनीतिक राय रखने से भी डरते हैं। यह कमाल है कि इतने असहिष्णु संगठन भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जता रहे हैं। ट्विटर के अकाउंट वैरिफिकेशन और कार्रवाई संबंधी मानक मनमाने हैं। इसका पता हाल में वेंकैया नायडू, मोहन भागवत आदि को ब्लू टिक से वंचित करने से चला। इसके पहले बंगाल हिंसा से आहत अभिनेत्री कंगना के ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में उत्तर देने संबंधी ट्वीट पर ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया, परंतु दिल्ली दंगों और लाल किले पर हुए राजद्रोह को ट्विटर पर मिले खुले उकसावे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह शर्जील उस्मानी के जय श्रीराम को आतंकवाद से जोड़ने वाले ट्वीट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मनमानी और पक्षपात से आगे बढ़कर तकनीकी कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या उनका भारत में अलगाववाद और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा और भारतीय कानून न मानने का हठ है। चाहे फिर ये कानून आपराधिक सामग्री, झूठे भड़काऊ संदेश, महिला उत्पीड़न के वीडियो आदि के मूल स्नोत जानने से संबंधित ही क्यों न हों। कुछ समय पहले कनाडा से चलाए गए खालिस्तान 2020 जनमत संग्रह अभियान को ट्विटर ने न सिर्फ पैसे लेकर प्रचारित किया, बल्कि इसकी शिकायत करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का ट्विटर हैंडल ही निलंबित कर दिया। आज जब भारत ने सूचना प्रसारण संबंधी नियमों के क्रियान्वयन की समयरेखा तय की है तो ये कंपनियां और खासकर ट्विटर कुछ ज्यादा ही हील-हुज्जत कर रहा है। जो कंपनियां अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और आस्ट्रेलिया में कानूनों को मानती हैं, जुर्माने भरती हैं और संसदीय समितियों के सामने दौड़कर पेश होती हैं, वे भारत को तिरस्कृत कर अपने नियमों की प्राथमिकता का हवाला दे रही हैं। टूलकिट मामले में तो जांच के लिए बुलाए जाने पर ट्विटर के क्षेत्रीय अधिकारी ने स्वयं को अमेरिकी कंपनी का कर्मचारी बताकर दिल्ली पुलिस को अमेरिकी ऑफिस से संपर्क करने की सलाह दे डाली। इस प्रकार भारतीय संप्रभुता की खिल्ली उड़ाकर ट्विटर ने यह दिखाने का प्रयास किया कि उसे भारतीय नियमों की कोई परवाह नहीं है।

ट्यूनीशिया, मिस्र आदि में अपनी दखलंदाजी से सत्ता परिवर्तन के बाद टेक कंपनियों के हौसले काफी बढ़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि जनमानस को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के चलते पूरा विश्वपटल उनके लिए खुला मैदान है। वे बड़े-बड़े नेताओं और चुनी हुई सरकारों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। आधुनिक युग के इन सामंतों में स्टुअर्ट मिल की पेचीदगी, मार्क्स की घातकता और किपलिंग की गोरी श्रेष्ठता कूट-कूटकर भरी है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार अपनी आजादी को इन नव-उपनिवेशवादियों के सामने गिरवी रखने को तैयार नहीं है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिग टेक माध्यम मात्र हैं और उस पर चर्चा नियमित करने का अधिकार सिर्फ भारत की चुनी हुई संसद को है।

सरकार को अब जो दे रहे नोट छापने की सलाह, तब वहीं मोदी के आर्थिक ज्ञान पर उठाएंगे सवाल

देश का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए तो नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखना उनके अस्तित्व के लिए जरूरी होता जा रहा है। मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हीं की राह पर उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी हैं। इनमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की आलोचना में मशगूल रहने वाले कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने एक नई सलाह दी है। उनका कहना है कि महामारी से उपजे आर्थिक हालात का मुकाबला करने के लिए सरकार को नोट छापने के विकल्प पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

दरअसल, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री डा. अभिजीत बनर्जी ने पिछले दिनों मोदी सरकार को नोट छापने की सलाह दी थी। उनके अलावा कई और अर्थशास्त्री भी यह सुझाव दे चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और उद्योग संगठन सीआइआइ के अध्यक्ष उदय कोटक भी इसी तरह की सिफारिश कर चुके हैं। पिछले हफ्ते जब एक प्रेस कांफ्रेंस में चिदंबरम से बनर्जी के इस सुझाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। जाहिर है, मोदी के घोर आलोचक अर्थशास्त्री डा. अभिजीत बनर्जी जिस रास्ते पर चलने की सलाह दे रहे हैं, उसका समर्थन तो चिदंबरम आंख मूंदकर करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसे अव्यावहारिक सिफारिशों पर कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। बनर्जी और चिदंबरम के अनुसार सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की चिंता किए बिना करेंसी नोट छापकर सरकारी खर्च को बढ़ाना चाहिए। कोविड के प्रभावित गरीबों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा नकदी पहुंचानी चाहिए, ताकि वे उन पैसों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदें और बाजार में मांग बढ़े और अर्थव्यवस्था की गाड़ी रफ्तार पकड़ सके। सुनने में तो यह अच्छा लगता है, लेकिन यह रास्ता जोखिम भरा है। प्रसंगवश बता दें कि वर्ष 1929-32 की महान मंदी के समय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जान मेनार्ड कीन्स ने सबसे पहले नोट छापकर सरकारी खर्च बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उस दौरान कीन्स के इस सिद्धांत को काफी अहमियत मिली। अनियंत्रित पूंजीवाद के कारण पैदा हुई मंदी की समस्या को दूर करने में उनका यह उपाय काफी हद तक सफल रहा था, लेकिन कालांतर में उनका यह सिद्धांत अर्थशास्त्रियों के बीच अलोकप्रिय होता चला गया। इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं। पहली नजर में तो यह सुझाव बहुत व्यावहारिक लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो इससे लाभ से ज्यादा नुकसान है। सबसे पहली बात तो यह है कि नोट छापकर सरकारी खर्च बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि इसमें वक्त लगता है, लेकिन नकदी हाथ में आते ही मांग तत्काल बढ़ जाती है। ज्यादा मांग और कम आपूर्ति के कारण महंगाई बढ़ने लगती है तो अंततोगत्वा अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित होती है। महंगाई बढ़ने से सरकारी बांड की कीमत गिरने लगती है और निवेशक उससे दूर होने लगते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है जो फिर महंगाई की आग में घी का काम करता है और इस तरह एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता है।

जहां तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सवाल है, तो मोदी सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही रास्ते पर चल रही है। लोगों के पास नकदी की कमी नहीं है। अभी रबी के सीजन में सिर्फ गेहूं की सरकारी खरीद के जरिए 76 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में गए हैं। पिछले एक साल की बात की जाए तो केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के जरिए जनता के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए यह लेन-देन होने के कारण 1.8 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है, जो दलालों और बिचौलियों की जेब में चला जाता था। अकेले पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिसंबर, 2020 तक 42 करोड़ गरीब लोगों के खातों में 68,903 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। लिहाजा, केंद्र सरकार को डा. अभिजीत बनर्जी और पी चिदंबरम जैसे विरोधियों की सलाह पर ध्यान देने के बजाय अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये वही विपक्ष है जिसने केंद्र को टीकाकरण के विकेंद्रीकरण की सलाह दी और जब ऐसा कर दिया गया तो हायतौबा मचा रहे हैं कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जाहिर है, आज जो लोग केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए नोट छापने की सलाह दे रहे हैं, कल जब इसके बुरे नतीजे सामने आएंगे तो केंद्र पर हमला करने में भी सबसे आगे रहेंगे और फिर चिदंबरम जैसों को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक ज्ञान को माचिस की डिबिया पर लिखा जा सकता है।

विरोध और आतंकवाद का फर्क

हाल के कुछ अहम फैसलों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे अदालतें लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा में लगी हुई हैं। राजद्रोह से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद मंगलवार को जामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा, पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कालीता को जमानत देने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी इस लिहाज से गौर करने लायक है। हालांकि मूलतः यह फैसला जमानत पर है, लेकिन अदालत ने इसमें कई ऐसी बातें कही हैं, जो व्यापक प्रभाव वाली हैं। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगाए थे, जिनका कोई ठोस सबूत वह अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई।

अदालत को कहना पड़ा कि ऐसा लगता है जैसे असंतोष को दबाने की चिंता में सरकार की आंखों के सामने वह रेखा धुंधली पड़ गई, जो विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को आतंकी गतिविधियों से अलग करती है। ध्यान रखना होगा कि यह मामला तब का है, जब दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए-एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। कुछ ही समय बाद दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक दंगे भड़के। पुलिस ने इन लोगों को दंगे भड़काने की साजिशों में शामिल बताया। केस अभी चल ही रहा है, मगर ताजा फैसले से जो पहलू सबसे महत्वपूर्ण रूप में उभरता है वह है यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के इस्तेमाल का।

चूंकि इस कानून के प्रावधान बहुत ज्यादा सख्त हैं और इसके तहत आरोपी को जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए भी यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसके इस्तेमाल में संजीदगी बरती जाए। अदालत ने ठीक ही कहा कि अगर थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाए कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध को व्यापक रूप देने की कोशिश की तो इससे ये आतंकवादी नहीं हो जाते। लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना सामान्य बात है और अक्सर ये विरोध कानून द्वारा तय किए गए दायरे से आगे भी निकलते रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो संबंधित लोगों पर कानून की वे धाराएं लागू की जानी चाहिए, जो उन मामलों में उपयुक्त हों। आतंकी गतिविधियों से जुड़ी धाराओं का सामान्य मामलों में इस्तेमाल लोकतंत्र में नागरिकों को दिए गए स्पेस को कम करता है।

इसीलिए अदालत ने आगाह किया कि अगर ऐसा होता रहा तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल, एक महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली दंगों की जांच का भी है। चूंकि पुलिस की साजिश की थिअरी न्यायिक समीक्षा में ठहर नहीं पा रही, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि वह दंगों की अपनी अब तक की जांच पर फिर से गौर करके उसकी कमियों को दूर करे। इस सवाल का सबूतों पर आधारित ठोस जवाब मिलना ही चाहिए कि राजधानी को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने वाले आखिर कौन थे।

कृषि निर्यात बढ़ने से किसानों की आमदनी और रोजगार के अवसरों में भी होगी वृद्धि

अब कृषि निर्यातकों के हितों के अनुरूप मानकों में उपयुक्त बदलाव भी करना होगा, ताकि कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से प्राप्त हो सके। सरकार को अन्य देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क की मुश्किलें जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कृषि निर्यात की संभावनाओं को साकार करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। कृषि निर्यात बढ़ने से देश के कुल निर्यात में वृद्धि होगी। इससे किसानों की आमदनी और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होगी।

हाल में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वित्त वर्ष 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में 7.3 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा, जिसने पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक लगातार विकास दर बढ़ने की प्रवृत्ति बताई। कोरोना की दूसरी घातक लहर से निर्मित हुई आर्थिक और औद्योगिक चुनौतियों के बीच देश के कृषि क्षेत्र में सुकून भरे तीन चमकीले आधार दिखाई दे रहे हैं। एक, फसल वर्ष 2020-21 से संबंधित तीसरे अग्रिम अनुमान में खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार बताई गई है। दो, खाद्यान्न तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात बढ़ गए हैं और तीन वर्ष 2021 में भारत में मानसून के अच्छे रहने की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं।

कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चालू फसल वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कोरोना की आपदा के बावजूद देश में खाद्यान्न की कुल पैदावार रिकार्ड स्तर पर पहुंचते हुए 30.54 करोड़ टन अनुमानित है। इस बार की अनुमानित खाद्यान्न पैदावार पिछले वर्ष की कुल पैदावार 29.75 करोड़ टन के मुकाबले 79.4 लाख टन अधिक है। यह महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष जब दुनिया के कई खाद्य निर्यातक देश कोरोना संकट के कारण खाद्य पदार्थों का निर्यात करने में पिछड़ गए थे, तब भारत ने विश्व खाद्य आपूर्ति शृंखला में कमी को रोकने का लक्ष्य रखते हुए खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ा दिया था। पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल से फरवरी के 11 महीनों के दौरान देश से 2.74 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। यह साल भर पहले की इसी अवधि के 2.31 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 16.88 फीसद ज्यादा रहा। इसके साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल-फरवरी के दौरान 26.51 प्रतिशत बढ़कर 43,798 करोड़ रुपये का हो गया। इन उत्पादों में दालें, प्रसंस्कृत सब्जियां, प्रसंस्कृत फल एवं फलों का जूस, मूंगफली, अनाज से बनी वस्तुएं, दुग्ध उत्पादन, अल्कोहल पेय और तेल खली आदि शामिल हैं।

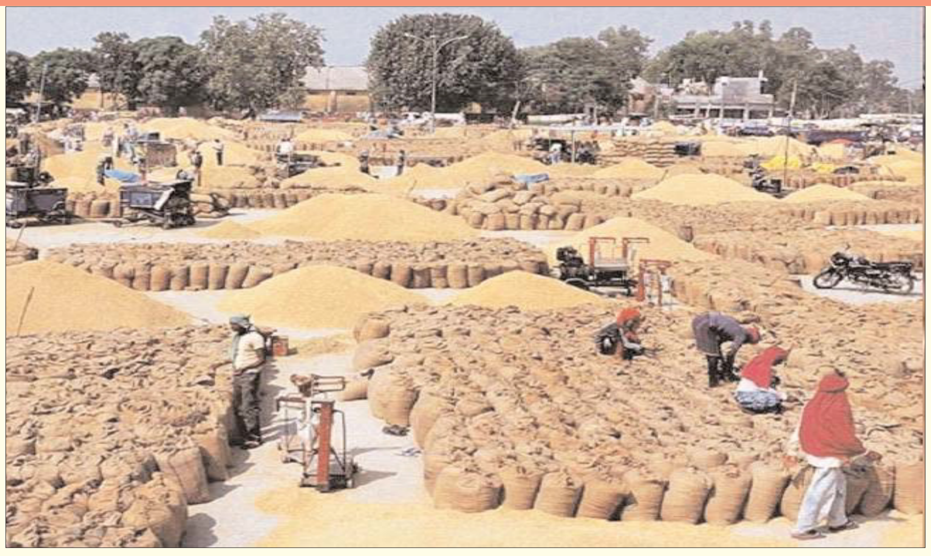

यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत के कृषिगत निर्यात पश्चिम एशिया, अमेरिका, ब्रिटेन यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजरायल, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न परंपरागत और नए देशों के बाजारों में अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने ब्राजील, चिली जैसे कई नए बाजारों में पकड़ बनाई है। खास बात यह भी है कि चीन ने भी भारत से बासमती चावल खरीदना शुरू किया है।

एक बार फिर अच्छे मानसून की संभावना के कारण आगामी फसल वर्ष में भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना दिखाई दे रही है। कोरोना के कारण आर्थिक मुश्किलों और गिरती विकास दर के बीच कृषि क्षेत्र संजीवनी की तरह उपयोगी दिखाई दे रहा है। कोविड की पहली लहर की चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था में कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जिसने वृद्धि की।

जहां कृषि क्षेत्र ने भरपूर खाद्यान्न भंडार से देश के लोगों को भोजन की चिंता से बचाया, वहीं अर्थव्यवस्था को ढहने से भी बचाया। महामारी के दौरान जहां देश की जीडीपी में बड़ी गिरावट आई, वहीं कृषि की विकास दर में करीब 3.4 फीसदी की वृद्धि होने से जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8 फीसदी से बढ़कर 19.9 फीसदी के स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए स्वीकृत किए गए 10,900 करोड़ रुपये के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। इस योजना से देश में मूल्यर्विधत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इससे विदेशी निवेश और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। किसानों को उनकी पैदावार के बेहतर दाम मिलने के साथ ही कृषि उपज की बरबादी को भी कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही इससे 2026-27 तक करीब ढाई लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। देश में जहां खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ाने में एमएसपी और विभिन्न कृषि विकास योजनाओं की अहम भूमिका है, वहीं कृषि निर्यात बढ़ने के भी कई कारण उभरकर दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति के तहत ज्यादा मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया है। सरकार ने निर्यात किए जाने वाले कृषि जिंसों के उत्पादन और घरेलू दाम में उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही राज्यों की कृषि निर्यात में ज्यादा भागीदारी, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार और नए कृषि उत्पादों के विकास में शोध एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया है। पिछले वर्ष से शुरू हुई किसान ट्रेनों ने भी कृषि निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

चालू वित्त वर्ष में कृषि उत्पादन के ऊंचाई पर पहुंचने की संभावनाओं के बीच कृषि निर्यात को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विभिन्न कृषि निर्यात अवरोध दूर किए जाने होंगे। इसके लिए संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से वार्ता तेजी से आगे बढ़ानी होगी। अब कृषि निर्यातकों के हितों के अनुरूप मानकों में उपयुक्त बदलाव भी करना होगा, ताकि कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से प्राप्त हो सके। सरकार को अन्य देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क की मुश्किलें जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कृषि निर्यात की संभावनाओं को साकार करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। कृषि निर्यात बढ़ने से देश के कुल निर्यात में वृद्धि होगी। इससे किसानों की आमदनी और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होगी।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

सागर: सड़क के किनारे खेत में पड़े मिले एक हिरण के अवशेष

सागर। सानौधा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार शाम मुख्य सड़क से लगे एक खेत के पास हिरण के अवशेष पड़े हुए मिले हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने अवशेष पड़े देखकर वन विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अवशेष काले हिरण के हैं जिसे कोई यहां फेंक कर चला गया है। जानकारी के अनुसार सानौधा निवासी शकंर आदिवासी के घर के सामने खेत में काले हिरण का अवशेष मिला है।

बड़वानी: बायोडीजल पंप में तोड़फोड़ और अपहरण के चार आरोपी गिरफ्तार

बड़वानी। जिले के सेंधवा स्थित एक बायोडीजल पंप पर पैसों के लेनदेन को लेकर इंदौर से आकर तोड़फोड़ और मारपीट कर चौकीदार का अपहरण करने के मामले में मुख्य आरोपी इंदौर निवासी कबीर सैयद, अनस अख्तर ,दीपक पिपलोदिया तथा राहुल कोठारे को मंगलवार की शाम गिरफ्तार कर लिया है। अभी सलमान फरार है। टीआई विकास कपीश ने बताया कि सेंधवा के बाहरी इलाके में स्थित आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरधारीलाल राठौर के बायोडीजल पंप के कार्यालय में तोड़फोड़, मारपीट व अपहरण के मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अपहृत चौकीदार धर्मेंद्र दसौंधी को भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरधारीलाल राठौर के बायोडीजल पंप में इंधन के लिए इंदौर के सप्लायर कबीर सैयद को एडवांस दिया था। जिसे वह लंबे समय से इसे नहीं लौटा रहा था। सोमवार की रात्रि मोबाइल फोन पर विवाद के बाद कबीर सैयद अपने साथियों के साथ बायोडीजल पंप के कार्यालय पर बंदूक की नोक पर जमकर तोड़फोड़ कर दी थी।

कटनी: जेल में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

कटनी। माधवनगर थाना के झिंझरी स्थित जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी राजकुमार पिता राधामोहन पटैल 40 निवासी पटौंहा रीठी का शव मंगलवार सुबह फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। कैदी का शव देख जेल प्रबंधन ने अधिकारियों को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। शव का पोस्टमार्टम कराया है। माधवनगर टीआई संजय दुबे ने बताया कि मृतक विचाराधीन कैदी 25 दिसंबर 2020 को कफ सिरफ रखने के आरोप में पकड़ा था। पुलिस के अनुसार 17 जून को राजकुमार को पैरोल पर छोड़ा था। उसे दोबारा 19 जून को जेल भेजा गया। कोरोना संक्रमण के चलते उसे जेल की अलग बैरक में रखा गया था। इसी बीच मंगलवार की सुबह जेल से पुलिस को सूचना दी गई कि विचाराधीन कैदी बैरक में गमछे से बने फंदे पर दरवाजे से लटका हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा बनाकर अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी ने कहा प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। मामले में जांच की जा रही है।

इंदौर: राशन में हेराफेरी के आरोपी संचालक को छह महीने की जेल

इंदौर। शहर के नेहरू नगर क्षेत्र में संचालित समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार से गरीबों को मिलने वाले राशन में हेराफेरी करने वाले संचालक व विक्रता प्रतीक नागवंशी को छह महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। राशन दुकान संचालक नागवंशी के खिलाफ चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 के तहत यह कार्रवाई कलेक्टर मनीषसिंह (डीएम) की कोर्ट द्वारा की गई। शासन द्वारा किसी गरीब या वंचित समुदाय के लिए दी गई राहत में हेराफेरी करने पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ समय पहले समता उपभोक्ता भंडार की जांच की गई थी। जांच के दौरान शासकीय राशन का भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें 49 क्विंटल गेहूं और 2 क्विंटल बाजरा कम पाया गया। साथ ही कई हितग्राहियों को पात्रता से कम राशन दिया गया। नागवंशी के खिलाफ एमआइजी थाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।

ग्वालियर: डिप्रेशन में युवती ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या

ग्वालियर। डिप्रेशन की शिकार युवती वायूनगर निवासी 32 वर्षीय ज्योति चंदोलिया पुत्री ओमप्रकाश चंदोलिया ने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने मौत की छलांग लगा दी। कनपटी के बल सड़क पर गिरी और उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर गोला का मंदिर ओम सांई अपार्टमेंट की है। सूचना मिलते ही युवती के परिजन स्पॉट पर पहुंच गए। उनका कहना था कि वह डिप्रेशन में थी और इलाज चल रहा था। दोपहर में वह घर से किसी दोस्त से मिलने जाने की कहकर निकली थी। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। गोला का मंदिर स्थित ओम सांई अपार्टमेंट के आसपास मंगलवार दोपहर सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक युवती अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की छत की मुढ़ेल पर खड़ी दिखाई दी। लोगों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उससे पहले ही युवती ने नीचे छलांग लगा दी। नीचे सड़क पर वह कनपटी के बल गिरी और वहीं हिचकी लेने के साथ उसकी मौत हो गई।

होटल में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बना रहे थे नकली शैम्पू

जबलपुर पुलिस ने यूपी के सात आरोपियों को दबोचा, बड़ी संख्या में खाली बोतलें जब्त

जबलपुर, (एजेंसी)। जबलपुर पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शैम्पू बनाने और उन्हें खपाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर सात युवाओं को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने कई बड़ी कंपनियों के खाली बोतल बरामद किया है।

ओमती थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नया मोहल्ला स्थित एक होटल में कुछ लोग दो कमरों को किराए पर लेकर वहां पर नकली शैंपू बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी एसपीएस सिंह बघेल ने अपनी टीम के साथ मौके पर दबिश। कमरे में शैंपू बनाने का सामान और कई ब्रांडेड कंपनियों की

खाली बोतलें मिली। पुलिस ने वहां से आगरा मोहम्मदी गेट निवासी सोनू मलिक, मोहम्मद आमीन, इकबाल, अरमान खान, अशफाक खान, मोहम्मद जकीर और इम्तियाज अली को पकड़ा जो कि आगरा उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं।

ऐसे चल रहा था कारोबार

दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से केमिकल को केन में भर कर ट्रेन से मंगाया जाता थाता था। ये केमिकल देखने में पानी जैसा लगता था। फिर इसमें सेलम का पाउडर, शैंपू बनाने का केमिकल, नमक और रंग का इस्तेमाल कर ब्रांडेड कंपनियों से मिलता-जुलता शैंपू तैयार करते थे। आरोपी पाउडर व केमिकल मिलाकर ब्रांडेड कंपनी के शैंपू जैसा कलर मिलाते थे। फिर डव, सनसिल्क, क्लीनिक प्लस, हेड एंड सोल्डर, पैंटीन कंपनी के नकली शैंपू बनाते थे। और फिर उस शैंपू को गरीब बस्तियों में जाकर कम कीमत में बेचा करते थे। कम दाम में ब्रांडेड कंपनियों के शैम्पू मिलने के झांसे में आकर लोग उसे हाथों हाथ खरीदा करते थे। लोगों से बोलते थे कि कंपनी को मॉल निकालना है, इस कारण डिस्काउंट दिया जा रहा है।

भोपाल में कोविड-19 परीक्षण के लिए एक व्यक्ति से स्वाब का नमूना एकत्र करती हुई।

हवाला के बाद सोने-चांदी की तस्करी के लिए हो रहा ट्रेनों का उपयोग

ताप्तीगंगा एक्सप्रेस में युवकों से सात करोड़ के सोने के आभूषण बरामद

डिलेवरी देने के पूर्व ही कटनी रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़े सूरत के तीन युवक

कटनी (एजेंसी)।

कटनी रेलवे पुलिस ने मंगलवार को करीब सात करोड़ रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा सोने के जेवरातों की बारीकी से जांच की जा रही हैं। युवक गुजरात के बताये जा रहे हैं।

ट्रेनों के जरिए हवाला कारोबार के साथ ही व्यापक पैमाने पर सोने व चांदी की तस्करी भी की जा रही है। इस बात का खुलासा देर रात लगभग ढाई बजे उस समय हुआ जब सूरत से चलकर कटनी पहुंची ताप्तीगंगा एक्सप्रेस से उतरते ही रेल पुलिस ने तीन युवकों को 13 किलो 900 ग्राम वजनी सोने के जेवर के साथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। युवकों के पास से बरामद सोने के जेवरों की कीमत लगभग सात करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में इतना पता चला है कि युवक यह सोने के जेवर शहर के ही किसी सराफा कारोबारी को देने आए थे लेकिन डिलेवरी देने के पूर्व ही वो रेल पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

उधर भारी मात्रा में सोने की खेप मिलने के बाद जबलपुर से रेल पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन भी कटनी के लिए रवाना हो गए हैं। इस संबंध में जीआरपी के प्रभारी थाना प्रभारी उपनिरीक्षक आरके पटेल ने बताया कि सूरत से भागलपुर के बीच कटनी होकर चलने वाली ताप्तीगंगा एक्सप्रेस में सोने की तस्करी होने की जानकारी मुखबिरों से मिली। जिसके बाद रेल पुलिस की टीम ट्रेन के कटनी पहुंचने के पूर्व ही सक्रिय हो गई। बताया जाता है कि देर रात लगभग दो-ढाई बजे जैसे ही ट्रेन कटनी पहुंची। इस ट्रेन से बाहर निकल रहे तीन युवकों को संदेह के आधार पर थाने ले जाया गया और उनके सामान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवकों के पास से अलग-अलग 13 किलो 900 ग्राम वजनी सोने के जेवर बरामद किए गए।

पड़ताल में जुटी आयकर विभाग की टीम

उपनिरीक्षक आरके पटेल ने बताया कि बिल के अनुसार आभूषण की कीमत 5 करोड़ 44 लाख 38 हजार 617 रुपए हैं। आभूषणों की कीमत वर्तमान बाजार मूल्य में लगभग सात करोड़ रुपए हैं। सोना बरामद होने की सूचना रेल पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन व आयकर विभाग की टीम को दी गई। जिसके बाद मंगलवार सुबह आयकर विभाग की टीम भी जीआरपी थाने पहुंच कर मामले की पड़ताल में जुट गई। वहीं युवकों से पूछताछ करने जबलपुर से रेल पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन भी कटनी के लिए रवाना हो गए हैं।

सराफा कारोबारी को देनी थी डिलेवरी

उपनिरीक्षक आरके पटेल ने बताया कि तीनों युवक धवल कुमार, अजय कुमार व पल्लोव पटेल सूरत के निवासी हैं। तीनों सोने के जेवरों की डिलेवरी देने कटनी आए थे। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि तीनों युवक शहर के किस सराफा कारोबारी को सोने के जेवरों की डिलेवरी देने आए थे।

प्रदेश में घट रहा कोरोना का संक्रमण, 31 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश में कोरोना के घटते संक्रमण के बीच, जहां मंगलवार को 65 नए मामले सामने आए, वहीं प्रदेश के 31 ऐसे जिले रहे, जहां कोरोना के एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। राज्य स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा यहां जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान 64,415 सेंपलों की जांच की गई, जिसके कोरोना के 65 नए मरीज मिले।

65 नए मरीज मिले, 20 की मौत

कोरोना की घटती रफ्तार के बीच सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आयी है। वर्तमान में प्रदेश भर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1707 रह गई है। इन नए मरीजों के मिलने के बाद प्रदेश में अब तक 7,89,415 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 318 नए मरीजों के स्वस्थ हो जाने के बाद अब तक 7,78,902 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 20 नए मरीजों की मौत हो जाने के बाद अब तक 8,806 मरीज अपनी जान गवां चुके हैं। इस बीच राजधानी भोपाल में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए, तो वहीं इंदौर में 12 नए मरीजों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। इन दोनों जिलों को छोड अन्य जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या दस से कम रही, जबकि धार, शिवपुरी, सतना, विदिशा सहित 31 जिलों में कोरोना के एक भी नए मरीज सामने नहीं आए हैं।

फर्जी रजिस्ट्री मामले मे उप पंजीयक एवं लेखक पर मामला दर्ज

सीधी। निजी भूमि का दोबार रजिस्ट्रेशन कराने के मामले मे विक्रेता सहित जिले के उप पंजीयक व रजिस्ट्री लेखक के विरुद्ध सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दिया है। ।

फरियादी अर्चना तिवारी पति पवन तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी दक्षिणी करोंदिया थाना जमोड़ी ने शिकायत कर बताया कि हरिलाल साहू निवासी महाराजपुर थाना कोतवाली से मैंने एक भूमि खरीदी थी जिसे हरिलाल द्वारा एक सप्ताह के भीतर ही पुनः लाभ कमाने के लालच में अखिलेश साहू निवासी महाराजपुर को बिक्री कर दिया है। थाना प्रभारी कोतवाली ने उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार को मामले की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। जांच में पाया गया कि उपरोक्त मामले में हरिलाल साहू के साथ साथ रजिस्ट्री लेखक एवं उप पंजीयक भी आरोपी हैं । जिसके बाद आरोपी हरिलाल साहू को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी भेजा है। तथा रजिस्ट्री लेखक एवं उप पंजीयक पर भी मामला दर्ज कर विवेचना जारी है।

श्योपुर में साले व साली की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले जीजा को दोहरी उम्रकैद

श्योपुर, (एजेंसी)। बड़ौदा थाना क्षेत्र के बागल्दा में पत्नि को लेने आए साले व साली से नाराज जीजा ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में श्योपुर कोर्ट ने आरोपी जीजा आदम खान निवासी प्रेमपुरा बागल्दा को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।

फरियादी नगिना उर्फ नग्नों ने पुलिस को बताया कि मेरे भाई व बहन लेने आए इस दौरान मेरे पति ने मेरे भाई एहसान व बहन शबाना को कुल्हाड़ी मार हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी जीजा आदम खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी। बता दें कि मामला 24 नबंबर 2018 को बड़ौदा थाना क्षेत्र के बागल्दा गांव में साली व साले बाइक से अपनी बहन को लेने पहुंचे और जीजा इस बात से नाराज होकर साले व साली को कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधिश द्वारा आरोपी आदम खान पुत्र शकुर मोहम्मद 32 वर्षीय निवासी प्रेमपुरा बागल्दा को दोहरे हत्याकांड का आरोपी दोषी टहराते हुए जिला न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

चलती ट्रेन की एसी बोगी ने निकलीं आग की लपटें, यात्रियों ने जंगल में रोकी ट्रेन

विशाखापटनम-हजरत निजामुद्दीन एक्स. की बी-2 बोगी के पैनल बोर्ड में लगी आग

डबरा, (एजेंसी)। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी धौलपुर ट्रेन पर मंगलवार को विशाखापटनम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस की एसी बोगी बी-2 में लगे पैनल बोर्ड में शार्ट सर्किट से आग लग गई। तेज गति से दौड़ रही ट्रेन के पैनल बोर्ड ने लगी आग से तेज लपटें निकलने लगी। कोच में सिर्फ 4 यात्री थे, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक दी। जिससे ट्रेन कोटरा एंव डबरा के बीच जंगल में खडी हो गई, इसके बाद ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टाफने आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को ट्रेन क्रमांक 02851 विशाखापटनम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस में दोपहर डेढ़ से पौने दो बजे के बीच कोटरा एवं डबरा के बीच ट्रेन के एसी कोच से आग की लपटें निकलती दिखाई देने पर एसी कोच क्रमांक बी-2 में मौजूद यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन सिंध नदी पुल के पास पोल क्रमांक 1175 पर जंगल में खड़ी हो गई। ट्रेन में मौजूद एस्कार्ट स्टाफ ने बोगी पर पहुंचकर बोगी को खाली कराया एंव ट्रेन में मौजूद फायर सिस्टम की सहायता से आग पर काबू पाया।

आगजनी से बोगी को काफी नुकसान हो चुका थां करीब आधा घंटे तक ट्रेन जंगल में खडी रही। इसके बाद ट्रेन को डबरा स्टेशन पर लाया गया, जहां झांसी से आए उत्तर मध्य रेलवे मंडल झांसी के अधिकारियों ने ट्रेन को चैक किया एंव यात्रियों से घटना के संबध में पूछताछ की। इसके बाद झुलसी हुई बोगी को ट्रेन से अलग किया गया। करीब ढाई बजे डबरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। इस तरह ट्रेन करीब एक घंटे लेट हो गई।

राजस्थान के धौलपुर पुलिस की मुरैना रेत माफिया से फायरिंग, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

मुरैना। बीती शाम धौलपुर में रेत बेचने गए माफिया ने वहां पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने वहां माफिया के दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

माफिया के लोग बीते रोज धौलपुर में रेत से लदे चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर गए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली का पीछा किया तो माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच भागते समय एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। बाकी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को लेकर रेत माफिया भाग निकले। माफियाओं का पुलिस लगातार पीछा कर रही थी। इसी बीच सबसे पीछे चल रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के टायर में पुलिस ने गोली मारी, जिससे वह धीमा हो गया। इस दौरान पुलिस ने अवैध चंबल रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर जब्त कर लिया। साथ ही रेत माफिया लालू उर्फ देवेंद्र पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर थाना सराय छोला मुरैना मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है।

आयुर्वेद डॉक्टरों को इमरजेंसी में एलोपैथिक दवाओं के प्रिस्क्राइब का मिले अधिकार

भोपाल, एजेंसी। कोरोना काल में आयुर्वेद डॉक्टरों ने भी काफी अच्छा काम किया है, आयुर्वेद दवाओं का उपयोग इस काल में अधिक तेजी से बढ़ा है। इसके मद्देनजर प्रदेश के आयुर्वेद डॉक्टरों ने एलोपैथिक दवाओं के प्रिस्क्राइब का अधिकार देने की मांग प्रदेश सरकार से की है।

प्रदेश सरकार से की मांग

आयुर्वेद डॉक्टरों ने बताया कि उत्तराखंड, उप्र, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाओं के प्रिस्क्राइब का अधिकार दिए हैं, जिससे मरीज के गंभीर होने पर उसे एलोपैथिक दवाओं के प्रिस्क्राइब लिखा जाए। इससे गंभीर मरीज की जान बचाने में सफलता मिलेगी। इन प्रदेशों की तर्ज पर ही मप्र सरकार को भी आयुर्वेद डॉक्टरों को इमरजेंसी में एलोपैथिक दवाओं के प्रिस्क्राइब का अधिकार देना चाहिए।

मंत्री मिश्रा ने दिया था आश्वासन: अब से साढ़े तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और अब गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र का अनुसरण कर आयुर्वेद डॉक्टरों को इमरजेंसी में जीवनरक्षक एलोपैथिक दवाओं के उपयोग की अनुमति देने को कहा था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं दी गई है। बीते 19 साल से प्रदेश के आयुर्वेद डॉक्टर्स यह मांग करते आ रहे हैं , मंत्री और मुख्यमंत्री से समक्ष कई बार मांग रखने के बाद भी उनकी मांग पर विचार तक नहीं किया गया है।

ऐसा कर सकती है सरकार

सरकार चाहे तो आयुर्वेद डॉक्टरों के स्वयं के खर्चे पर तीन से छह माह की विशेष ट्रेनिंग भी देकर एलोपैथिक दवाओं के प्रिस्क्राइब लिखने का अधिकार दे सकती है। इसका लाभ ग्रामीण इलाकों में मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में आयुर्वेद डॉक्टर्स ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

इनका कहना है

उत्तराखंड, उप्र, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर मप्र सरकार को भी आयुर्वेद डॉक्टरों को इमरजेंसी में एलोपैथिक दवाओं के प्रिस्क्राइब का अधिकार देना चाहिए, जिससे खास तौर पर ग्रामीण इलाके के मरीजों की अपातकाल स्थिति में जान बचाई जा सके।

डॉ. राकेश पांडेय, अध्यक्ष, आयुर्वेद पीजी एसोसिएशन मप्र

प्रयागराज में संगम के पास बड़े हनुमान जी मंदिर में बड़ा मंगल के अवसर पर पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए भक्त ।

बक्सवाहा का मामला — महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, मांगा जवाब

हीरा खदान के लिए एनटीसीए व वाईल्ड लाइव बोर्ड की नहीं ली अनुमति

जबलपुर (एजेंसी)।

छतरपुर में नेशनल टाईगर कंजरवेटर अथॉरिटी व बाईल्ड लाइव बोर्ड की अनुमति बगैर टाईगर कॉरीडोर में हीरा खदान के लिए बक्सवाहा जंगल की जमीन आवंटित किए जाने को चुनौती देने वाले मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया।

चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार की उन दलीलों को नकार दिया, जिसमें कहा था कि उक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं है। युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। यह जनहित का मामला हरियाणा फरिदाबाद निवासी रमित बासु, महाराष्ट्र पुणे निवासी हर्षवर्धन मेलांता व उप्र निवासी पंकज कुमार की ओर से दायर किया है। जिसमें कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हीरे की खदान के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की एस्सल माइनिंग एंड इंड्रस्ट्री को छतरपुर स्थित बक्सवाहा के जंगल की 382 हैक्टेयर जमीन 50 साल की लीज के लिए प्रदान की गयी है। हीरा उत्खनन के लिए रेन फारेस्ट के लगभग सवा दो लाख पेड़ों को काटा जायेगा। जबकि उक्त जंगल पन्ना टाईगर रिजर्व से लगा हुआ है, जो टाईगर कॉरीडोर में आता है।

इसके लिये एनटीसीए व बाईल्ड लाइव बोर्ड से अनुमति भी नहीं ली गई। आवेदकों का कहना है कि वनजीवों को जीवन का अधिकार प्राप्त है और वो जंगल में रहते है। जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो वनप्राणी कहां रहेंगे। बक्सावाहा के जंगल में बड़ी संख्या में वन सम्पदा है और ऐसे जंगल पनपने में हजारों साल लगते है। राज्य सरकार ने लाभ के लिए जंगल की जमीन को लीज पर दिया है, जो गलत निर्णय है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि एनटीसीए की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योकि उक्त जंगल पन्ना टाईगर रिजर्व से 50 किमी. दूर है।

वहीं मामले में आवेदकों की ओर से कहा गया कि उक्त पूरी प्रकिया के लिये उक्त विभागों की अनुमति की आवश्यकता है वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 38 (ओ) व 38 (बी) में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया, जिसके तहत टाईगर कॉरीडोर में माइनिंग जैसी किसी भी गतिविधि के लिये वाईल्ड लाईव बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। पर्यावरण वन मंत्रालय के सचिव, प्रमुख सचिव खनिज संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव फॉरेस्ट विभाग, पीसीसीएफ व एनटीसीए, कलेक्टर छतरपुर व एस्सल माइनिंग एंड इंडस्ट्री के एमडी आदित्य बिरला को पक्षकार बनाया है। मामले की सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस देकर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

शिवसागर के विधायक और आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई को गुवाहाटी में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में पेश किया गया।

चेन्नई के कलैवनार आरंगम में 16वें तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षाकर्मी।

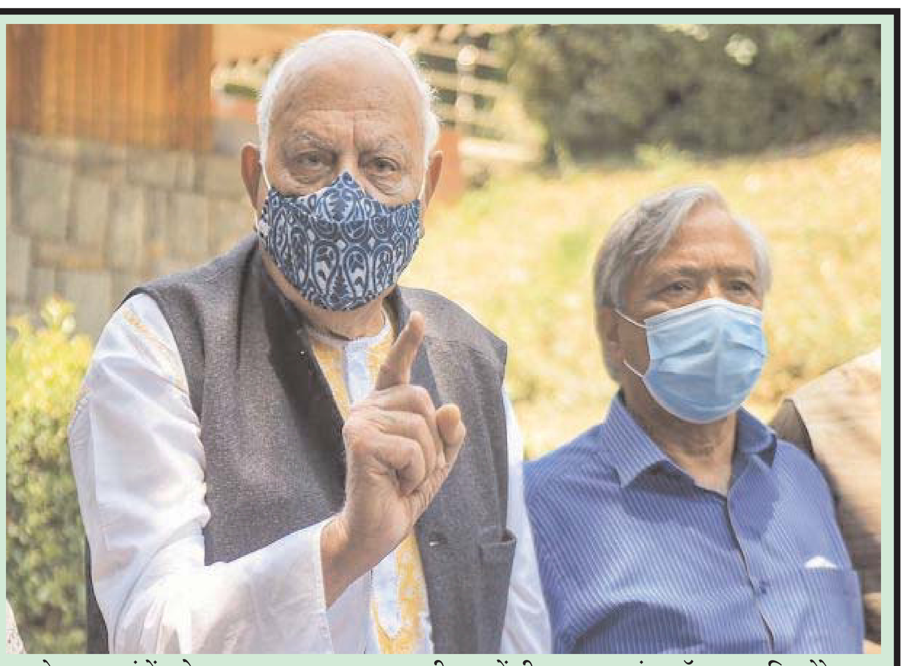

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए।

एक नजर

ममता की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस ने खुद को किया अलग

नई दिल्ली । नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि ममता ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए इजाजत नहीं देने के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ आज ममता और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा दायर अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई करने वाली थी। अब इस मामले की दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा मामले में हलफनामा दायर करने की इजाजत देने से मना करने के बाद ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ममता बनर्जी को इस मामले में पक्षकार बनाया गया था जब सीबीआइ ने तृणमूल कांग्रेस के चार मंत्रियों को गिरफ्तार किया था और वह सीबीआई कार्यालय पहुंची थीं।

पिछले महीने, नारद घोटाले में टीएमसी के चार मंत्रियों - फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मामला एक स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है, जिसे आमतौर पर नारद स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें ये पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टिंग करने वाले शख्स सैमुअल से अवैध रूप से रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मलय घटक द्वारा दायर अपील पर 22 जून को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने 18 जून को कोलकाता हाईकोर्ट से अनुरोध किया था वह शीर्ष अदालत द्वारा आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के एक दिन बाद मामले की सुनवाई करे। 9 जून को, कलकत्ता हाई कोर्च की पांच-जजों की पीठ ने नारद स्टिंग टेप मामले को विशेष सीबीआइ अदालत से उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वह चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन ममता बनर्जी और घटक की भूमिका को लेकर उनके द्वारा दायर हलफनामे पर विचार करने के बारे में बाद में फैसला करेगी।

महाराष्ट्र में तेजी से पैर पसार रहा है डेल्टा प्लस वैरिएंट, 21 लोग संक्रमित

मुंबई । कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूटी और इसकी चपेट में आने से हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। अब कोरोना का डेल्टा प्लस वैरिएंट जन्म ले चुका है ये दुनिया के कई देशों में पैर पसार चुका हैं वही भारत में भी ये संक्रमण फैलता जा रहा है। डेल्टा प्लस नाम का ये वैरिएंट महाराष्ट्र में अब तक 21 लोगों को संक्रमित कर चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार सबसे ज्यादा नौ मामले रत्नागिरी में, इसके बाद जलगांव में सात, मुंबई में दो और पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग जिलों में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। राजेश टोपे ने बताया राज्य के विभिन्न भागों से 7,500 नमूने एकत्र किए गए और प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। मंत्री ने कहा कि ये नमूने 15 मई से एकत्र किए गए थे और उनका जीनोम अनुक्रमण किया गया था। जीनोम अनुक्रमण SARS-CoVw से छोटे उत्परिवर्तन (वायरस के स्वरूप बदलना) का भी पता लगाया जा सकता है। टोपे ने कहा कि डेल्टा प्लस वैरिएंट के साथ पाए गए लोगों के बारे में पूरी जानकारी मांगी जा रही है, जिसमें उनका यात्रा का विवरण भी शामिल है इसके अलावा क्या उन्हें टीका लगाया गया था या नहीं, और क्या वे फिर से संक्रमित हुए थे। उनके संपर्क में आये लोगों का भी पता लगाया जा रहा है और उनका परीक्षण किया जा रहा है, मंत्री ने कहा कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के उत्परिवर्तन की जानकारी की भी जांच की जा रही है। पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि नए पहचाने गए डेल्टा प्लस संस्करण राज्य में महामारी की तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं। हालांकि नए संस्करण के कारण बीमारी की गंभीरता का अभी तक कोई संकेत नहीं है।

ओडिशा की बहू बनी गोरखपुर की बेटी- घरवालों ने दर्ज करवाया अपहरण का केस; लड़की ने किया खारिज

भुवनेश्वर । उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के खार बार थाना क्षेत्र की बेटी ओडिशा की बहू बनी है। ओडिया लड़के के प्रेम करने के बाद लड़की ने अपना घर परिवार को त्याग कर भुवनेश्वर आ गई और यहां अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। हालांकि लड़की का पीछा करते हुए पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस को खाली हाथ वापस लौट जाना पड़ा है। घर वालों द्वारा अपहरण का आरोप लगाने के मामले को लड़की ने सिरे से खारिज कर दिया है। लड़की ने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से यहां आयी हूं, यहां आने के बाद हमने शादी कर ली है और यहीं पर रहूंगी। खबर के मुताबिक भुवनेश्वर में रहने वाले युवक पृथ्वीराज पंडा और उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के खारबार थाना क्षेत्र की आकांक्षी सिंह दोनों प्रेम करते हैं। दोनों ने शादी का निर्णय लिया। इसके बाद आकांक्षी ने अपने प्रेम के बारे में परिवार को बताया। हालांकि परिवार लोग इस पर राजी नहीं हुए। यहां तक कि उसे प्रताड़ना देने लगे, जो आकांक्षी ने खुद कहा है। आकांक्षी ने पुलिस को बयान दिया है कि इससे तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने से पहले परिवार के उद्देश्य से एक पत्र लिखा था। इसमें हमने लिखा था कि अपनी मर्जी से मैं छोड़कर ओडिशा जा रही हूं। यहां मैं अपने प्रेमी के साथ शादी करूंगी। आकांक्षी अपने साथ अपना आधार कार्ड और सर्टिफिकेट लेकर आयी। आकांक्षी सिंह गोरखपुर से नई दिल्ली गई और फिर यहां से भुवनेश्वर आयी। भुवनेश्वर में पहुंचने के बाद उसने अपने प्रेमी पृथ्वीराज के साथ कोर्ट मैरेज कर ली। वहीं दूसरी तरफ लड़की के अपहरण होने का एक मामला आकांक्षी के परिवार वालों ने गोरखपुर खारबार थाना में दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस आकांक्षी को लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंची।

ओडिशा में कोरोना संक्रमण के 3031 नए मामले, 43 लोगों ने तोड़ा दम

भुवनेश्वर । ओडिशा में कोरोना संक्रमण अब धीरे-धीरे कम होने लगा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3031 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं जबकि 43 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या पिछले काफी दिनों से 40 के ऊपर रह रही है, जो चिंता का विषय है। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक खुर्दा जिले में सर्वाधिक 381 लोग संक्रमित मिले हैं जबकि कटक जिले से 295, बालेश्वर जिले से 290, भद्रक जिले से 135, अनुगुल जिले से 121, बरगड़ जिले 39, बलांगीर जिले से 30, बौद्ध जिले से 40, देवगड़ जिले से 11, ढेंकानाल जिले से 90, गजपति जिले से 25, गंजाम जिले से 26, जगतसिंहपुर जिले से 107, जाजपुर जिले से 226, झारसुगुड़ा जिले से 17, कालाहांडी जिले से 39, कंधमाल जिले से 38, केन्दुझर जिले से 118, केन्दुझर जिले से 68 लोग संक्रमित मिले हैं।

वैक्सीन, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को सुरक्षित करेगा एम्बिटैग

नई दिल्ली । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ (आईआईटी रोपड़) ने अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक आईओटी डिवाइस- एम्बिटैग का विकास किया है। यह डिवाइस खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन और यहां तक कि शरीर के अंगों व रक्त को ले जाने के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करती है। दर्ज किए गए इस तापमान से यह जानने में सहायता मिलती है कि दुनिया में कहीं भी भेजा गया कोई सामान तापमान में अंतर के कारण अभी तक उपयोग के योग्य है या खराब हो गया है। कोविड-19 वैक्सीन, अंगों और रक्त के परिवहन सहित वैक्सीन के लिए यह जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

एडब्ल्यूएडीएच परियोजना समन्वयक डॉ. सुमन कुमार ने बताया कि यूएसबी के आकार की डिवाइस, एम्बिटैग एक बार रिचार्ज होकर पूरे 90 दिन के लिए किसी भी टाइम जोन में -40 से +80 डिग्री तक के वातावरण में निरंतर तापमान दर्ज करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध इस तरह की डिवाइस सिर्फ 30-60 दिनों तक की अवधि के लिए तापमान दर्ज करती हैं। उन्होंने कहा कि जब तापमान पूर्व निर्धारित सीमा से ऊपर जाता है तो यह एक अलर्ट जारी करती है। दर्ज किए गए डाटा को किसी कंप्यूटर को यूएसबी से जोड़कर हासिल किया जा सकता है। डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार हब एडब्ल्यूएडीएच (कृषि एवं जल तकनीकी विकास हब) और उसके स्टार्टअप स्क्रैचनेस्ट के तहत विकसित किया गया है। एडब्ल्यूएडीएच भारत सरकार की एक परियोजना है। प्रो. कुमार ने कहा कि यह डिवाइस आईएसओ 13485-2016, ईएन 12830-2018, सीई और आरओएचएस से प्रमाणित है।

सब्जियों, मीट और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाले उत्पादों के अलावा यह परिवहन के दौरान जानवरों के सीमेन के तापमान की भी निगरानी कर सकता है। स्क्रैचनेस्ट के संस्थापकों और निदेशकों में से एक अमित भट्टी ने कहा कि अभी तक, ऐसी डिवाइसों को भारत में सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, आयरलैंड और चीन जैसे दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है।

एडब्ल्यूएडीएच परियोजना निदेशक, प्रो. पुष्पेंद्र पी. सिंह ने बताया कि आईआईटी रोपड़ प्रौद्योगिकी नवाचार हब एम्बिटैग के व्यापक उत्पादन की तैयारी कर रहा है। प्रो. सिंह ने कहा कि यह डिवाइस कोविड वैक्सीन के उत्पादन केंद्र से देश के किसी भी कोने में स्थित टीकाकरण केंद्र तक ढुलाई में लगी सभी कंपनियों को 400 रुपये की उत्पादन लागत पर उपलब्ध होगी।

यह डिवाइस इस अभूतपूर्व महामारी में देश के लिए हमारी तरफ से छोटा सा योगदान है और इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलता है।

अलगाववादी शब्बीर शाह की जमानत याचिका का इडी ने किया विरोध, कहा- कश्मीर में अशांति के लिए धन जुटाने में था शामिल

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान के साथ-साथ कई अन्य देशों से धन जुटाने की अपराध में शामिल रहा है। दिल्ली की एक अदालत में शाह की जमानत याचिका पर अपने जवाब में इडी ने कहा कि वह भी आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों में शामिल था। आतंकवादियों को आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि मनी-लॉन्ड्रिंग वह तरीका है, जिसके द्वारा अपराधी अपने धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाते हैं और अपने संपत्ति और ठिकानों की रक्षा करते हैं, ताकि जांच एजेंसियों के संदेह से बचा जा सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा द्वारा मामले की सुनवाई मंगलवार को 29 जून के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि शाह का वकील व्यक्तिगत कारणों के चलते सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं था।

इडी के जवाब के अनुसार, आरोपी शब्बीर अहमद शाह पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के हाफिज सईद प्रमुख के नियमित संपर्क में था। जमात-उद-दावा को यूएनसी द्वारा प्रतिबंधित संगठन है जो सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। उसने यह भी बताया कि शब्बीर अहमद शाह मोहम्मद शफी शायर के संपर्क में था, जो कश्मीर का है और सेंट्रल जेल जम्मू से छूटने के बाद अपने परिवार के साथ पाकिस्तान भाग गया था। इडी ने यह भी कहा कि जमानत याचिका पर दायर करने वाले के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। मामले में आगे की जांच चल रही है और संपत्तियों की पहचान की जा रही है। पैसे कहां से आए इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है। पाकिस्तान से संबंधित कॉल रिकॉर्ड और मेल की जांच की जा रही है। धन मुहैया करने देने वाले लोगों की पहचान और जांच की जानी है। यदि आरोपी को इस समय जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो बड़ी साजिश का पता लगाने का पूरा प्रयास व्यर्थ होगा।

छत्तीसगढ़ में नक्सली मोर्चे पर कामयाबी, दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर

दंतेवाड़ा । छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तीन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें से एक के सिर पर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया था। अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नक्सली मोर्चे पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि कैडर 2015 से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाने, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाने सहित दंतेवाड़ा और पड़ोसी सुकमा जिलों के अंदरूनी इलाकों में माओवादी पोस्टर और बैनर लगाने में कथित रूप से शामिल थे। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि सोमवार को पुलिस के पहुंचने से पहले तीनों ने सरेंडर कर किया। सभी

नक्सलियों ने पुलिस के पुनर्वास अभियान लोन वरातु से प्रभावित होकर सरेंडर किया। वह सभी खोखली माओवादी विचारधारा से निराश हो गए हैं। उन्होंने बताया कि तीनों नक्सलियों में से आयता कोहरामी नाम की महिला एक मीलिटा कमांडर के रूप में सक्रिय थी, जिसके सिर पर 1 लाख रुपये का इनाम था। जबकि दो अन्य कैडरों की पहचान उईका सोमदू (23) और करतम महेंद्र (22) के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि महेंद्र 2018 में तिम्मापुरम गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में भी वांछित था। इस सरेंडर के साथ ही 375 नक्सलियों ने लोन वरातु अभियान के तहत जिलें में हिंसा छोड़ दी। जिनमें से 99 लोगों के सिर पर नकद ईनाम रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि इस पहल के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ने कम से कम 1,600 नक्सलियों के पैतृक गांवों में पोस्टर और बैनर लगाए हैं, जिनमें ज्यादातर नकद इनामी हैं और उनसे मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा रही है।

कोरोना वैक्सीन लेने के लिए ग्राहकों को ऑफर दे रही कई प्राइवेट कंपनियां

नई दिल्ली । किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोरोना महामारी किसी तरह के ऑफर का भी जरिया बन सकेगी। लेकिन इस महामारी ने इसको भी सच कर दिया है। दरअसल, अब प्राइवेट कंपनियां और बड़े ब्रांड्स अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर लाने में जुट गए हैं। देश के उत्तर और पूर्व में मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने अपने मोबाइल एप पर वी केयर के नाम से इसकी शुरुआत कर दी है। कंपनी इसके जरिए कोरोना वैक्सीन ले चुके अपने ग्राहकों को कम से कम 500 रुपये के ऑर्डर पर 20 फीसद तक की छूट का ऑफर दे रही है। उत्तर-पूर्व भारत में इसका संचालन करने वाली कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स के सीओओ राजीव रंजन का कहना है कि देश में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ये कदम बेहद खास है। उनका कहना है कि ब्रांड के तौर कंपनी का अपने ग्राहकों से गहरा जुड़ाव है और कंपनी को इस बात की भी खुशी है कि वो देश को महामारी से उबारने में सहायक साबित हो रहे हैं। ये एक अनोखा तरीका है जिसके जरिए हम इस काम में योगदान दे रहे हैं।

मैक्डोनाल्ड के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम के कई रेस्टोरेंट भी अपने ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने के लिए इसी तरह का ऑफर दे रहे हैं। इस तरह का ऑफर देने वाली कंपनियों का मकसद भले ही इसके जरिए अपना बिजनेस बढ़ाना है लेकिन उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि वो इसके लिए वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरुक करने में भी कामयाब हो सकेंगे। ऑनलाइन किराना स्टोर ग्रोफर्स ने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए इसी तरह के ऑफर का सहारा लिया है। ग्रोफर्स ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनीसेफ से गठजोड़ किया है। ग्रोफर्स अपने ऑफर के जरिए उन लोगों को जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है, उन्हें एक माह के लिए फ्री में एसबीसी (स्मार्ट बचत क्लब) की सदस्यता दे रहा है। इस स्कीम के जरिए ग्राहकों को कई तरह की छूट मिल सकती है।

ऐसा की ऑफर लेकर डीटीएच सेवा प्रदाता डिश टीवी भी सामने आया है। ये कंपनी अपने ग्राहकों को एक दिन का एंटरटेनमेंट मुफ्त में मुहैया करवा रही है। अब इन कंपनियों के अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उन लोगों के लिए शुरू की जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले रखी है, के लिए पिछले महीने से एक सावधि जमा योजना इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम लागू की है। इस स्कीम का मैच्युरिटी टाइम 1,111 दिनों का है और इसके तहत ग्राहकों को 5.35 फीसद ब्याज देती है जबकि मूल ब्याज दर 5.1 फीसद है।

त्रिपुरा के दो गावों में सभी लोगों को लगा कोरोना टीका, सीएम ने बोले- जल्द पूरे राज्य का हो जाएगा टीकाकरण

अगरतला । देश में कोरोना टीकाकरण में तेजी आने के बीच खबर है कि त्रिपुरा के दो गावों में सभी पात्र लोगों का टीकाकरण हो गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने बताया है कि उत्तरी त्रिपुरा जिले के जुबराजनगर ब्लॉक में मंगलखली ग्राम पंचायत और त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के मोहनभोग ब्लॉक में पूर्णा चंडीगढ़ ग्राम पंचायत में वैक्सीन के लिए सभी पात्र लोगों का टीककारण हो गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि जल्द ही पूरे त्रिपुरा का टीकाकरण हो जाएगा।

देब ने ट्वीट करके कहा कि त्रिपुरा कोविड-19 के खिलाफ लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर त्रिपुरा जिले के जुबराजनगर ब्लॉक के अंतर्गत मंगलखली ग्रामपंचायत अब पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गया है। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द पूरे राज्य को वैक्सीनेट करने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सिपाहीजला जिले के मोहनभोग ब्लॉक में पूर्णा चंडीगढ़ ग्राम पंचायत भी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गया है। ये तो बस शुरुआत है, जल्द ही पूरे त्रिपुरा का टीकाकरण हो जाएगा।

भारत में एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना टीकाकरण- मंगलखली ग्राम पंचायत की कुल 2,339 आबादी में से 18-44 आयु वर्ग के 903 लोग वैक्सीन लेने के लिए पात्र थे। त्रिपुरा सरकार ने ग्राम पंचायत उप-केंद्र में 867 टीका लगाए, जबकि शेष 36 को राज्य के अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में टीका लगाया गया। जिला प्रशासन ने पहले ही 9 अप्रैल तक मंगलखली ग्राम पंचायत की 45 साल से अधिक पूरी आबादी का टीकाकरण कर दिया था। बता दें कि सोमवार को भारत में लोगों को वैक्सीन की 86,16,373 खुराक दी गई, जो दुनिया में एक दिन में अब तक का सबसे अधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी।

कोविड वैक्सीनेशन पर हावी न होने दें किसी भी खास ब्रांड के टीके की चाहत

नई दिल्ली । आमतौर पर कोई किसी टीके के ब्रांड के बारे में जानने का खास इच्छुक नहीं होता है। हम में से शायद ही किसी को पता हो कि हमें किसी फ्लू के लिए लगा टीका किस ब्रांड का था। लेकिन, कोरोना के मामले में ऐसा नहीं है। कोरोना का कहर फैलने के बाद पिछले साल ही कंपनियां टीका बनाने में जुट गई थीं। ट्रायल पूरा करने के बाद आज कई कंपनियों के टीके उपलब्ध हो चुके हैं। आए दिन खबरों में लोगों को अलग-अलग ब्रांड के बारे में पढ़ने को मिलता रहता है। यही जानकारी कुछ मामलों में मुश्किल का कारण बन रही है, क्योंकि कुछ लोग खास टीका लगवाने के इंतजार में टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। खास टीके का इंतजार गलत - विशेषज्ञों का कहना है कि सभी टीके तय प्रक्रिया और मानक के अनुसार बनाए जाते हैं। हर देश में सरकार नियमानुसार टीकों को मान्यता देती है। ऐसे में किसी खास ब्रांड के इंतजार में टीकाकरण नहीं कराना गलत है। सबसे अच्छा टीका वही है, जो आपको सबसे पहले मिल जाए।

हर टीके का काम आपको संक्रमण के संभावित खतरे से बचाना है। कुछ कम या ज्यादा प्रतिशत के साथ सभी टीके प्रभावी हैं। सुरक्षा के मानकों पर भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है। ऐसे में किसी खास टीके के इंतजार में रुके रहना आपको खतरे में डाल सकता है।

समर्थन में अलग-अलग तर्क - किसी खास ब्रांड के टीके के समर्थन में अलग-अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका के टीके को कुछ लोग देशप्रेम से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि यह वहीं की कंपनी है।

अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन के लिए भी इंटरनेट मीडिया पर लोग खूब तर्क दे रहे हैं। ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है, जो रूस के स्पुतनिक-वी टीके का इसलिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एफिकेसी ज्यादा पाई गई है। भारत में उपलब्ध टीके- एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित व सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन यहां उपलब्ध हैं। रूस की स्पुतनिक- वी को मंजूरी दी जा चुकी है। वैश्विक स्तर पर प्रमाणित टीकों के भारत में प्रयोग से जुड़े नियमों में कुछ नरमी से अन्य कंपनियों के टीकों के आने की उम्मीद भी बढ़ गई है।

सचिन पायलट ने बदली रणनीति, जातिगत समीकरण साध कर बनाएंगे दबाव, किसान सम्मेलन करने की योजना

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी संग्राम का कांग्रेस आलाकमान कोई हल नहीं निकाल पा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अब राज्य की राजनीति में दखल रखने वाली तीन मजबूत जातियों जाट, मीणा और गुर्जर का गठजोड़ बनाने की रणनीति बनाई है। पूर्वी राजस्थान के गुर्जर और मीणा बाहुल्य इलाकों में पहले से ही पायलट की मजबूत पकड़ है। इस क्षेत्र के दो दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में ये दोनों जातियां चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करती है। पायलट आगामी दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के गुर्जर, मीणा बाहुल्य इलाकों में जाने की योजना बना रहे हैं।

फिलहाल, इन इलाकों में उनकी पकड़ कमजोर है। इसी के साथ वे जाट बाहुल्य नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर, सीकर जिलों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिहाज से युवाओं के संपर्क में है। इन जिलों से 4 जाट युवा विधायक पायलट के खेमे हैं। इन्ही विधायकों के सहारे वह जाट समाज में पहुंच बनाने में जुटे हैं। पायलट की योजना है कि जुलाई और अगस्त माह में 33 में से एक दर्जन जिलों का दौरा कर आलाकमान एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बनाया जाए। लोगों के बीच जाकर पायलट उनकी समस्याएं जानेंगे और फिर सरकार की घेराबंदी करेंगे।

यह बात पायलट भी जानते हैं कि विधायकों की संख्या के लिहाज से वे सीएम गहलोत के मुकाबले पीछे हैं। लेकिन एक किसान नेता के रूप में आम लोगों के बीच उनकी पहचान है। दो दर्जन जिलों में उनकी हमेशा मांग रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दो दर्जन जिलों के प्रत्याशियों ने पायलट की सबसे ज्यादा मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पायलट ने गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने और छोटे-छोटे किसान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। आगामी दिनों में पायलट लाव लश्कर के साथ दौरे शुरू करेंगे।

गहलोत समर्थक जी-19 की बैठक में बनेगी रणनीति- गहलोत समर्थक 13 निर्दलीय व बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों की बुधवार को जयपुर में बैठक होगी। बैठक में विधायक गहलोत के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने के साथ ही दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने पर निर्णय लेंगे। ये विधायक पहले ही कह चुके हैं कि अगर हम समर्थन नहीं करते तो गहलोत सरकार पहले ही गिर गई होती।

गुजरात में बीते 24 घंटे में दर्ज हुए 151 नए मामले, 5639 मरीज सक्रिय

अहमदाबाद । गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 151 नए मामले सामने आए जबकि दो और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में सोमवार को रिकॉर्ड 4 लाख 87960 लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में अब तक दो करोड़ 25 लाख 56262 टीके लगाए जा चुके हैं। यहां कोरोना संक्रमण से अब तक 10034 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कुल 8 लाख 6812 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 5639 है। राज्य के विविध महानगरों में कोरोना के केस इस प्रकार हैं अहमदाबाद महानगर पालिका में 36 केस एक की मौत, सूरत महानगर पालिका में 16 केस 1 की मौत, राजकोट नो वडोदरा 7 जूनागढ़ महानगर पालिका 3 जामनगर दो तथा भावनगर वह गांधीनगर मालिक महानगर पालिका में 1-1 केस आया है। विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के केस प्रकार हैं जूनागढ़ 10, सूरत 10, वडोदरा 10, वलसाड 6, भरूच पांच गिर सोमनाथ 5, कच्छ 5, पंचमहाल 4, अमरेली, देवभूमि द्वारका, खेड़ा राजकोट में 3-3, आनंद दो मेहसाणा दो नवसारी दो भावनगर जामनगर पोरबंदर में एक एक केस सामने आया है।

लक्ष्य हमेशा एक फिल्म से ज्यादा रही है

फिल्म 'लक्ष्य' को आज अपनी रिलीज के 17 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर ने फिल्म के लिए अपनी प्रेरणा साझा की है और साथ ही, फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मदद के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया है। फरहान अख्तर ने यह भी उल्लेख किया कि लक्ष्य हमेशा उनके लिए एक फिल्म से ज्यादा रही है। फरहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रितिक रोशन, अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए फरहान ने कैप्शन में लिखा, मैं हमेशा इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार रहूंगा हमें सपोर्ट करने के लिए और अविश्वसनीय रूप से समर्पित और दृढ़ कास्ट और क्रू मेंबर्स का जिन्होंने मेरे इस जीवन अनुभव में सहयोग दिया है। मैं इसे फिल्म नहीं कहूंगा, क्योंकि ये हमेशा उससे भी बढ़कर रहेगी। लक्ष्य के 17 साल। बता दें कि फिल्म 'लक्ष्य' में प्रीति जिंटा के साथ रितिक रोशन ने अहम भूमिका निभाई थी, कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर स्थापित यह एक काल्पनिक कहानी थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली व एक कल्ट वॉर फिल्म में तब्दील हो गई और आज भी फिल्म प्रेमियों के बीच पसंदीदा बनी हुई है।

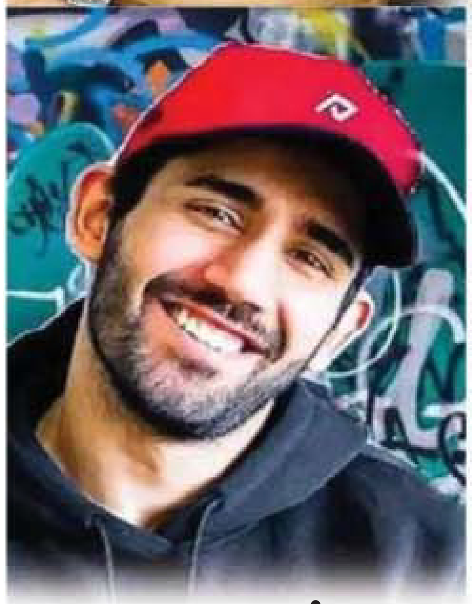

खतरनाक स्टंट करते वक्त चोटिल हुए वरुण सूद

रोहित शेट्टी के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' की शूटिंग इन दिनों केप टाउन में चल रही हैं। शो के कंटेस्टेंट्स सेट से कई सारी तस्वीरें और वीडियो फैंस के लिए शेयर करते रहते है। वहीं अब खतरों के खिलाड़ी के सेट से एक बुरी खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार कंटेस्टेंट वरुण सूद चोटिल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि एक खतरनाक स्टंट करते हुए वरुण सूद तीन से चार दिन पहले चोटिल हो गए थे। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वरुण को हाथ में चोट लगी थी। सभी को लग रहा था कहीं फ्रेक्चर न हुआ हो, लेकिन अस्पताल में एडमिट कराने के कुछ घंटों बाद ही वह अच्छी महसूस कर रहे थे। वरुण को 2 से 3 दिनों तक आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन वह उसी दिन सेट पर जा पहुंचे। बता दें कि वरुण सूद ने साल 2015 में रियलिटी शो 'रोडीज' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह एमटीवी स्प्लिट्सविला में भी नजर आएं। 'खतरों के खिलाड़ी' के इस सीजन कई फेमस सेलेब्रिटीज शामिल हुए हैं। इसमें दिव्यांका त्रिपाठी, श्वेता तिवारी, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, अभिनव शुक्ला, सौरभ राज जैन, विशाल आदित्य सिंह, आस्था गिल, सना मकबूल, महक चहल शामिल हैं।

बिग बॉस 15 की शुरू हुई तैयारी, इस बार 6 महीने चलेगा शो!

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' के हर सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि बिग बॉस 15 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस शो से जुड़े अपडेट्स हरदिन सामने आते रहते हैं। खबरें है कि इस बार शो 3 महीने नहीं, बल्कि 6 महीने तक चल सकता है। बताया जा रहा है की ओटीटी की डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने ये फैसला लिया है कि शो का पहला भाग ओटीटी प्लेटफार्म वूट पर रिलीज किया जाएगा, जिसमें शुरुआत में 12 कंटेस्टेंट नजर आएंगे। जब ये शो टीवी पर प्रसारित किया जाने वाला होगा उस दौरान इस शो में से 8 कंटेस्टेंट को एविक्ट किया जाएगा और सिर्फ 4 कंटेस्टेंट को टीवी के शो में एंट्री मिलेगी। हर एविक्शन के बाद इस शो में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री भी होगी। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हर बार की तरह इस इस सीजन को भी सलमान खान होस्ट करते नजर आएंगे। वहीं खबरें हैं कि मेकर्स इस बार शो को और ग्रैंड बनाने के लिए 'बिग बॉस 15' में एक से ज्यादा कपल्स नजर आएंगे, वहीं दूसरी बार शो में कुछ आम लोगों को भी कंटेस्टेंट बनने का मौका मिलेगा।

विक्टोरिया सीक्रेट के साथ जुड़ीं प्रियंका चोपड़ा, कहा– मेरे लिए बहुत रोमांचक है

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस का सिक्का विदेशों में भी चलता है। इस बीच प्रियंका चोपड़ा का नाम उन सितारों की लिस्ट में शुमार हो गया है, जो विक्टोरिया सीक्रेट के साथ जुड़ी हैं। विक्टोरिया सीक्रेट ने अपनी सुपर मॉडल्स (जिन्हें एंजेल्स भी कहते हैं) से दूरी बनाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए कदम आगे बढ़ाया है।

विक्टोरिया सीक्रेट संग जुड़ीं प्रियंका चोपड़ा

बता दें कि विक्टोरिया सीक्रेट सुपर मॉडल्स से दूरी बनाते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए फीमेल एथलीट्स, एक्टिविस्ट्स और एंटरप्रेन्योर आदि को मौका दे रहे हैं। इस बीच विक्टोरिया सीक्रेट के सोशल मीडिया से कुछ नए मेंबर्स के नाम सामने आए हैं। इस लिस्ट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल है।

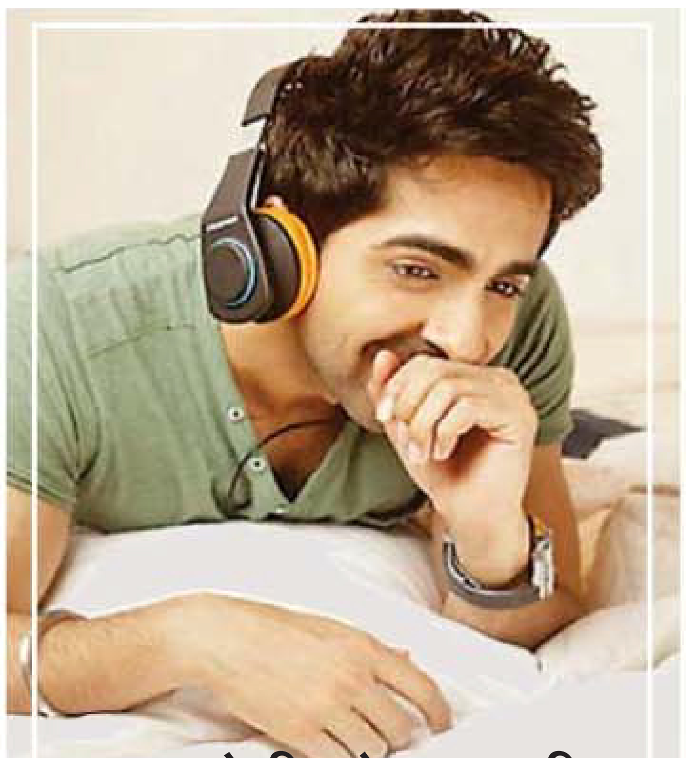

आज मेरी जो कुछ भी इक्विटी है, सोशल एंटरटेनर के तौर पर मेरी सफलता की वजह से है

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना की लोकप्रियता में हाल के वर्षों के दौरान लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि उन्होंने सिनेमाघरों में बैक टू बैक आठ हिट फिल्में दी हैं। भारत में समावेशी, बातचीत शुरू करने वाले सोशल एंटरटेनर के रूप उनकी बढ़ती विश्वसनीयता ने उन्हें देश के सबसे अधिक डिमांड वाले ब्रांड एंडोर्सर्स में शामिल कर दिया है। अब, आयुष्मान को एक मोबाइल फोन ब्रांड ने अपना चेहरा बनाया है। मोबाइल फोन और बैंकिंग दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां कलाकार के चेहरे की विश्वसनीयता बेहद मायने रखती है। हाल ही में मोबाइल फोन ब्रांड्स ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर और विराट कोहली जैसे सुपरस्टार्स को साइन किया है। इसलिए, मोबाइल फोन ब्रांड द्वारा आयुष्मान को अपना चेहरा बनाए जाने का निश्चित तौर यह मतलब है कि लोगों में उनकी विश्वसनीयता बढ़ रही है। आयुष्मान से यह पूछे जाने पर कि ऐसी कौन सी खूबी है जो उन्हें इतना ब्रांड फ्रेंडली बनाती है, उन्होंने कहा, आज जो कुछ भी मेरी पहचान है, वह विशेष रूप से सोशल एंटरटेनर के तौर पर मेरी सफलता की वजह से है, जिसने मुझे भारत के लोगों से जोड़ा है। मेरी फिल्मों ने लोगों को बताया है कि मैं कौन हूं, कैसा सोचता हूं और एक एंटरटेनर के तौर पर मेरा उद्देश्य क्या है।

वह आगे कहते हैं, सोचकर अच्छा लगता है कि ब्रांड्स ने इसको नोटिस किया है और वास्तविक लोगों की असली कहानियों को पेश करने की मेरी कोशिश के विचार से जुड़े हैं। इस बात को लेकर मैं रोमांचित महसूस कर रहा हूं कि एक नरेटिव के साथ दर्शकों तक पहुंचने के लिए मैं ब्रांड के विजन और उनके सफर का हिस्सा हूं, जो मेरे सिनेमा में प्रतिध्वनित होती है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें लोगों का प्यार व तारीफें भी मिली हैं। आयुष्मान कहते हैं कि वह खुशकिस्मत रहे हैं कि उन्हें सही फिल्में मिलीं जो बहुत बड़ी हिट साबित रहीं। उनका मानना है कि सफलता हमेशा इक्विटी में तब्दील होती है। आयुष्मान कहते हैं, मैंने हमेशा इस सोच में विश्वास किया है कि मैं नहीं बल्कि मेरा काम बोले। मैं उन प्रोजेक्ट्स को चुनने के लिए भाग्यशाली रहा हूं, जिन्होंने भारत में सिनेमा किस तरह यूनिक, लीक को तोड़ने वाला, बातचीत को शुरू करने वाला एंटरटेनर हो सकता है, इस मान्यता को स्थापित करने में योगदान दिया है, जिन्हें कहानियों को बयां करने के लिए रूढ़िवादी मानदंडों का पालन करने की जरूरत नहीं है।

मुंबई को बंद देखना विचलित करने वाला है

बॉलीवुड अभिनेता ताहिर राज भसीन आखिरकार तीन महीने बाद शहर में वापस आ गए हैं और उन्होंने काम फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'लूप लापेटा' की डबिंग शुरू कर दी है। अभिनेता का कहना है कि महामारी के दौरान एक हलचल भरे शहर को ठप होते देखना विचलित करने वाला है। उन्होंने कहा, ''मुंबई में वापस आकर और देश की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद काम शुरू करना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मुंबई में एक बहुत ही अलग ऊर्जा है और मैंने यहां अपने हर समय को प्यार किया है। यह एक ऐसा शहर है जिसने मुझे हवा दी है मेरे पंखों के नीचे रचनात्मक रूप से आकांक्षा और ऊंची उड़ान भरने के लिए। वह आगे कहते हैं, ''मैंने 'लूप लापेटा' के लिए डबिंग शुरू कर दी है। जैसे ही मैं इसे पूरा कर लूंगा, मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करूंगा, जिसे लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। इससे पहले मैं अपने ब्रांड की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा हूं।'' अभिनेता का कहना है कि उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में शूटिंग के लिए मुंबई छोड़ दिया था क्योंकि शहर में मामले बढ़ रहे थे। मुंबई को सामान्य स्थिति में वापस आते देखना और उद्योग को फिर से शुरू करना बहुत अच्छा है। ताहिर का कहना है कि जब मुंबई में शूटिंग रोकी गई तो उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने कहा, ''यह सपनों का शहर है और यह दिन के हर सेकंड में हमेशा चालू रहता है। यह मुंबई का आकर्षण है। इसलिए, इसे बंद देखना, फिल्म उद्योग का ठप होना और लोगों के लिए काम नहीं करना विचलित करने वाला है।'' 'लूप लपेटा' में ताहिर की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ है। उनके पास सोनाक्षी सिन्हा के साथ 'बुलबुल तरंग' और श्वेता त्रिपाठी के साथ 'ये काली काली आंखें' भी हैं।

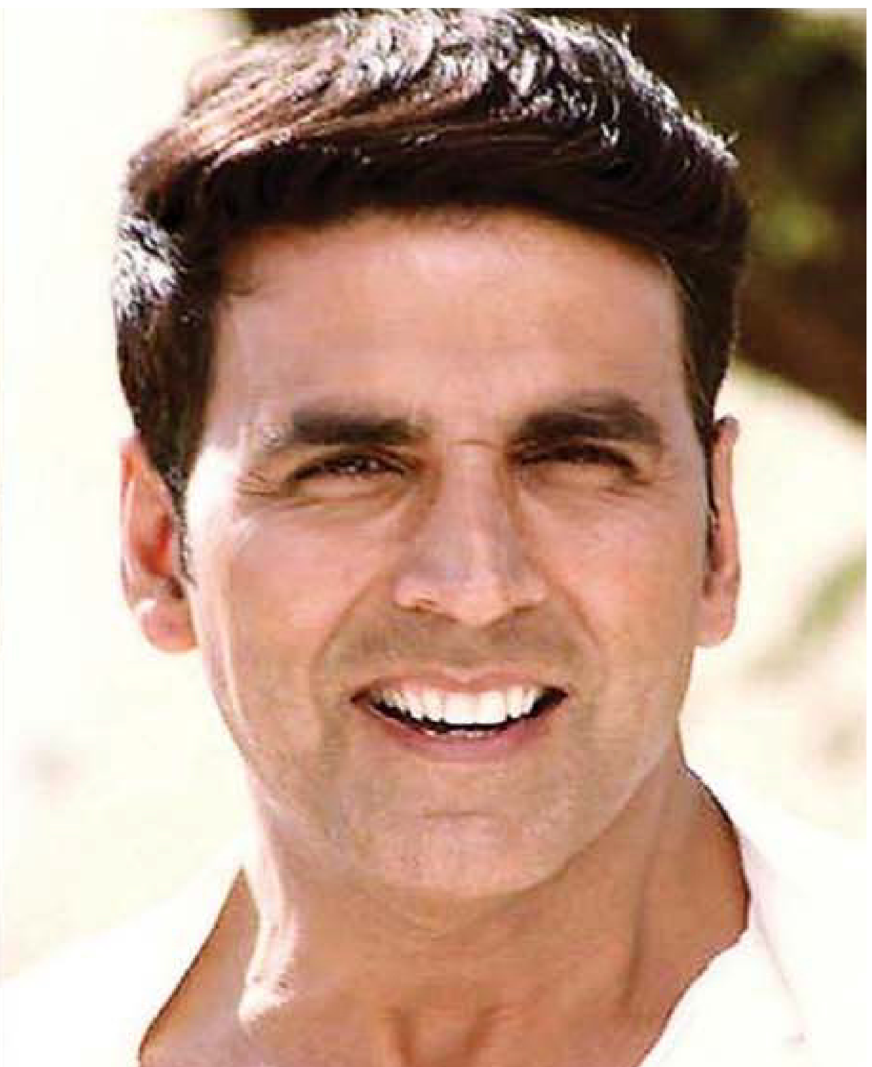

फिर विवादों में घिरी अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज

अक्षय कुमार बॉलीवुड के बिजी एक्टर में से एक हैं। आने वाले समय में उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली है, जो अलग-अलग जॉनर की है। इन्ही में से एक फिल्म 'पृथ्वीराज' है। यह फिल्म राजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी और उनकी वीरता पर आधारित है। अक्षय कुमार की यह फिल्म घोषणा के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों करणी सेना ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी। करणी सेना का कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म महान पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित है। ऐसे में फिल्म का नाम पृथ्वीराज कैसे रखा जा सकता है। वहीं अब करणी सेना के बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने फिल्म के नाम को लेकर आपत्ति जताई है। क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोगों का कहना है कि फिल्म का नाम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान या सम्राट पृथ्वी राज चौहन होना चाहिए। फिल्म का नाम सिर्फ 'पृथ्वीराज' नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान देते हुए उनका पूरा नाम होना चाहिए। खबरों के अनुसार क्षत्रिय महासभा न चंडीगढ़ में फिल्म के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षत्रिय महासभा ने अक्षय कुमार और फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी का पुतला भी जलाया। संगठन से जुड़े लोगों ने यह भी मांग की कि फिल्म रिलीज होने से पहले क्षत्रिय और राजपूत समाज से जुड़े प्रतिनिधियों को यह फिल्म दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि फिल्म में किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं। बता दें कि इससे पहले करणी सेना ने कहा था कि फिल्म टाइटल को बदला जाए और महान राजा पृथ्वीराज को सम्मान दिया जाए। करणी सेना ने आगे शर्त रखते हुए कहा था कि इस फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें फिल्म दिखाई जाए। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो वो इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहें। फिल्म पृथ्वीराज की बात करें तो इस फिल्म को चंद्रप्रकाश द्रिवेदी निर्देशित कर रहें हैं। फिल्म अक्षय कुमार के साथ मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। फिल्म में वह संयुक्ता का किरदार निभा रही हैं। मानुषी की यह बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है।

दीपिका पादुकोण ने ए चेन ऑफ वेलबीइंग किया लॉन्च यूनिसेफ का मिला साथ

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने आज अपने सोशल मीडिया पर 'ए चेन ऑफ वेलबीइंग' लॉन्च किया है, जो एक डिजिटल गाइड है और उन चीजों को आगे लाने पर केंद्रित है, जो लोगों को समग्र निराशा / भारीपन से निपटने में सहायता करेगी, विशेष रूप से आज के कठिन वक्त में। 'ए चेन ऑफ वेलबीइंग' दीपिका ने इंस्टाग्राम के 'गाइड्स' फीचर का इस्तेमाल करते हुए 'ए चेन ऑफ वेलबीइंग' की चेक लिस्ट को कंपाइल किया है। इसका परिचय देते हुए उन्होंने लिखा, ''ध्यान रखने के लिए एक रिमाइंडर।' इसके साथ ही अभिनेत्री द्वारा कई अन्य सोशल मीडिया हैंडल के सहयोग से वेलबींग गाइड लॉन्च किया गया है, जो एक समान लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में मदद मिल सके।

यूनिसेफ संग भागीदारी

'संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी' यूनिसेफ, भारत ने भी कई अन्य डिजिटल प्रभावितों के साथ ''चेन ऑफ वेलबीइंग'' के लिए अभिनेत्री के साथ भागीदारी की है। हाल ही में, यूनिसेफ इंडिया ने दीपिका और 'द लिव लाफ लव फाउंडेशन' को टैग करते हुए अपने सोशल मीडिया पर 'मैनेजिंग ट्रॉमा एंड लॉस' पर एक गाइड साझा की थी। अन्य कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्लुएंसर्स ने भी अभिनेत्री की पहल 'विटामिन स्ट्री', 'द आर्टिंडोट', 'सुनाक्षा अय्यर' इत्यादि का समर्थन करने के लिए अपने सोशल मीडिया पर इसी तरह के पोस्ट साझा किए हैं।

'वेलनेस गाइड' पहले भी किया था लॉन्च

इसका इरादा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीडर्स और शक्तिशाली आवाजों के साथ एक गाइड तैयार करना है जो जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करेगा। इससे पहले भी, दीपिका ने मई 2020 में कोविड – 19 की पहली लहर के दौरान सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के साथ सहयोग करते हुए 'वेलनेस गाइड' को लॉन्च किया था।

बात दीपिका पादुकोण के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करें तो वो जल्दी ही ऋतिक रोशन के साथ फिल्म फाइटर में नजर आएंगी। ऋतिक रोशन के अलावा दीपिका पादुकोण की जोड़ी शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान में भी बनेगी। पठान में शाहरुख और दीपिका के साथ जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। फाइटर और पठान के अलावा दीपिका के खाते में द इंटर्न और 83 भी शुमार है। याद दिला दें कि द इंटर्न में अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे।

सभी आरोप निराधार, मुझे पूर्वनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया : मनु साहनी

दुबई, (एजेंसी)। वर्तमान में कदाचार के आरोपों को लेकर निलंबित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनु साहनी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है।

उन्होंने दावा किया कि वह एक पूर्व नियोजित साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा उनके खिलाफ हो रही जांच एक घोटाला और प्रताड़ना का प्रयास है।

साहनी ने 17 जून को हुई अनुशासनात्मक सुनवाई के विस्तृत जवाब में यह तर्क दिया है कि उन्हें सुनवाई की निष्पक्ष प्रक्रिया से वंचित और मूल न्याय के सिद्धांतों को अनदेखा कर दिया गया है। उन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया को भी घोटाला करार दिया है। निलंबित सीईओ ने सोमवार को एक बयान में कहा मुझे स्पष्ट और अच्छी तरह पता है कि मैं एक पूर्व नियोजित प्रताड़ित योजना का शिकार हुआ हूं।

निष्पक्ष प्रक्रिया शुरू करने और मुझे निष्पक्ष सुनवाई देने के आश्वासन का सारा ढोंग पूरी तरह से बंद हो गया है। आईसीसी की आंतरिक नीतियों और यहां तक कि मूल न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि साहनी को 9 मार्च को चार विशिष्ट आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया था। उन पर कुछ कर्मचारियों को लक्षित रूप से धमकाने, शारीरिक रूप से प्रभाव दिखाने, अपने व्यवहार के जरिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने और आईसीसी को रिपोर्ट करने में विफल रहने और उचित परामर्श के बिना निर्णयों को लागू करने के आरोप हैं।

ये सभी आरोप प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निष्कर्षों पर आधारित थे, जिसे आईसीसी में एक स्वतंत्र सांस्कृतिक मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था।

आईसीसी के निलंबित सीईओ ने कहा मेरा मानना है कि यह मेरी और आईसीसी की ईमानदारी के लिए महत्वपूर्ण है कि मैं मुझे पद से हटाने के इस प्रयास का विरोध करूं, जो एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम करेगा।

निलंबित आईसीसी सीईओ ने कहा मैं यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं कि मेरे कार्यकाल के दौरान आईसीसी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इतिहास से बाहर नहीं किया जाएगा।

मुझे अपील करने का अधिकार है। मैं आईसीसी की अनुशासनात्मक नीति के पैराग्राफ 7 और मेरे रोजगार अनुबंध के खंड 17।4 के अनुसार बोर्ड को किसी भी दोषी निर्णय की अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा।

ओमाहा नेब में यूएस ओलिंपिक स्विम ट्रायल्स की वेब 2 के दौरान पुरुषों की 50 फ्रीस्टाइल जीतने के बाद खुशी जताते कैलेब ड्रेसेल।

सोहैब और सोहेल के शानदार प्रदर्शन से पीएसएल-6 के फाइनल में पहुंचा मुल्तान सुल्तांस

दुबई, (एजेंसी)। सोहेल तनवीर और ब्लेसिंग मुजरबानी के 3 विकेट और सोहेब मकसूद के जुझारू अर्धशतक ने मुल्तान सुल्तांस को पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 6 के फाइनल में पहुंचा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 19 ओवर में 149 रन पर ढेर कर सुल्तान्स को क्वालीफायर में 31 रन से जीत मिली। सुल्तान्स ने पिछले साल पीएसएल प्लेऑफ में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन क्वालीफायर में कराची किंग्स और एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स से हारने के बाद बाहर हो गई थी, इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की।

2016 और 2018 का विजेता रहे यूनाइटेड के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका होगा, क्योंकि वे मंगलवार शाम को एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 के विजेता से भिड़ेंगे। 181 रनों के अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए टूनाइटेड ने तीन ओवरों के भीतर 3 विकेट खो दिए जिसमें से 2 विकेट सोहेल के थे। यूनाइटेड 10वें ओवर में फॉर्म में चल रहे उस्मान ख्वाजा के हुसैन तलत को ज्वाइन करने पहले 5 विकेट पर 61 रन बनाए थे। इस जोड़ी ने 6 विकेट के लिए 28 गेंदों में 50 रन का योगदान दिया।

सोहेल ने उस्मान का बेशकीमती विकेट लेकर मैच को पलटने में अहम भुमिका निभाई थी। उस्मान ने 40 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था। जिम्बाब्वे के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मुजरबानी ने इफ्तिखार अहमद (15 गेंदों में 16 रन), हुसैन तलत (25 गेंदों में 25 रन) और फहीम अशरफ (शून्य) सहित कुल तीन विकेट लेकर 31 रन देकर शानदार गेंदबाजी की। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सोहेल ने 17 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए।

इससे पहले पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद सुल्तान्स ने सोहैब के पीएसएल 6 में चौथे अर्धशतक के दम पर पांच विकेट पर 180 रन बनाए। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए 41 गेंदों में से 59 रन बनाए जिसमें 7 चौके और तीन छक्के शामिल थे। शान मसूद (22 गेंदों पर 25 रन) और रिले रोसौव (शून्य) का विकेट गंवाने के बाद सुल्तान टीम ने सोहैब ने चौथे विकेट के लिए जॉनसन चार्ल्स (21 गेंदों में 41 रन) के साथ 63 रन की साझेदारी की।

कप्तान मोहम्मद रिजवान इससे पहले पारी के दूसरे ओवर में शून्य पर आउट हो गए थे। खुशदिल शाह (22 गेंदों पर नाबाद 42 रन) ने पारी के 19वें ओवर में 4 छक्के जड़े जिससे सुल्तान्स को शानदार स्कोर बनाने में मदद मिली। उन्होंने छठे विकेट के लिए सोहेल (9 गेंदों पर नाबाद 12 रन) के साथ नाबाद 43 रन की साझेदारी की। यूनाइटेड के लिए फहीम अशरफ और शादाब ने दो-दो विकेट लिए।

वॉकी टॉकी पर बात करते दिखे सिराज, लोगों ने कहा कि बुमराह को टिप्स दे रहे हो

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का मौका नहीं मिला। सिराज इस समय टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच डब्ल्यूटीसी फाइनल का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया है। मैच के पहले दिन का खेल बारिश में धुल गया था जबकि दूसरे और तीसरे दिन कुछ खेल संभव हो पाया। चौथे दिन भी साउथम्प्टन में बरसात होती रही और दिन के खेल को रद्द करना पड़ा। भारतीय टीम पहली पारी में 217 रन पर ढेर हो गई, जबकि कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। भारतीय गेंदबाज पहली पारी में प्रभावशाली नहीं रहे। वह कीवी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके। इसकारण ओपनर डेवोन कॉन्वे अर्धशतक जड़ने में सफल रहे। इस बीच भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज का एक ऑफ फील्ड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सिराज वॉकी टॉकी पर किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सिराज को हाथ में वॉकी टॉकी लिए स्टैंड में बैठे हुए देखा जा सकता है। सिराज के इस वीडियो को देख फैंस ने जमकर मजे लेने शुरू कर दिए। एक फैंस ने कॉमेंट किया, बुमराह को टिप्स दे रहे हो। दूसरे ने टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की फोटो अपलोड कर लिखा, ओए कोच को उठाओ। बारिश के कारण डब्ल्यूटीसी फाइनल के ड्रॉ होने की संभावना बढ़ गई है। रिजर्व डे को मिलाकर अगले दो दिन भी बारिश की भूमिका अहम रहेगी। यदि यह टेस्ट ड्रॉ होता है,तब दोनों टीमों को ज्वाइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा।

अपहरण कांड पर मैकगिल ने तोड़ी चुप्पी, कहा-मैंने कुछ भी गलत नहीं किया

सिडनी, (एजेंसी)। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल ने इस साल की शुरूआत में अपने अपहरण और हमले पर खुलकर बात की और पुलिस को बताई गई कहानी को बिल्कुल सच बताया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर को अप्रैल में अपहृत करके बंदूक की नोक पर निर्वस्त्र किया और उनके साथ मारपीट की और धमकाया। इसके बाद अपहताओं ने उन्हें मुक्त कर दिया था। संन्यास ले चुके स्पिन गेंदबाज ने बताया कि 14 अप्रैल को सिडनी के उत्तरी तट पर क्रेमोर्न में उनके घर के पास से उनका अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद अपहताओं ने उन्हें निर्वस्त्र कर उनके चेहरे और सिर के पिछले हिस्से पर मुक्के मारे। मैकगिल ने घटना की रिपोर्ट करने के लिए 5 दिन इंतजार किया, इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई।

हाल ही में प्रसारित एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मारिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर लोग मेरे और पुलिस दोनों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के विपरीत कुछ और सोचना चुनते हैं तो यह उनके ऊपर है।

पुलिस ने कहा मैकगिल ने कथित अपहरण से पहले अपने पार्टनर के भाई को एक प्रतिष्ठित ड्रग डीलर से मिलवाया था, जिसे पुलिस सन्नी के नाम से जानती थी। इस 50 वर्षीय पूर्व लेग स्पिनर ने कहा हम खुद को निर्दोष मानते हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों को इमारत के मामले में अन्य लोगों से मिलवाते हैं, जिससे आयोजन स्थल के आसपास थोड़ी भीड़ पैदा होती है और आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। दो बच्चों के पिता मैकगिल ने कहा उन्हें दोस्तों ने निराश किया है। उन्होंने कहा, इससे मेरे परिवार को ठेस पहुंची है और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं हम दोनों को एक ही स्थिति में देख सकता हूं। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है।

पहली अमेरिकी ओलंपिक स्केटबोर्डिंग टीम के 8 सदस्य लॉस एंजिल्स शहर में एक समाचार सम्मेलन के लिए अपने बोर्ड पर पहुंचे।

नस्लवाद बड़ी समस्या, ब्रिटेन में बड़ा हुआ होता तो शायद आज जिंदा ही नहीं होता : माइकल होल्डिंग

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने एक विवादास्पद बयान दिया है। होल्डिंग ने कहा अगर वह यूके में बड़े हुए होते तो शायद आज जिंदा ही नहीं रहे होते। अमेरिका में पिछले साल हुई जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही होल्डिंग रंगभेद को लेकर काफी मुखर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन ने अपने देश में नस्लवाद रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। होल्डिंग ने कहा अगर वह ब्रिटेन में बड़े हुए होते तो अपने उग्र व्यवहार के चलते जवानी में ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती। महान तेज गेंदबाज ने कहा अगर मैं यूके में होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज जिंदा होता। जवानी में मैं थोड़ा उग्र था। अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए होल्डिंग ने कहा कि जमैका में उन्हें नस्लवाद का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि 67 वर्षीय इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि जब भी वह उस स्थान से बाहर गए तो उन्हें इसका अनुभव हुआ। उन्होंने कहा जमैका में बड़े होते हुए, मुझे कभी नस्लवाद का सामना नहीं करना पड़ा। जब भी मैं जमैका से बाहर गया तो मुझे इसका अनुभव हुआ। हर बार जब मुझे इसका अनुभव हुआ तो मैंने खुद से यही कहा यह तुम्हारी जिंदगी नहीं है, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने कोई स्टैंड लिया होता तो मेरा करियर इतना लंबा नहीं हो पाता। मेरा टेलीविजन करियर भी इतना लंबा नहीं होता। उन्होंने कहा हमने देखा है कि ब्लैक लोग जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए, जिन्होंने अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई। ईश्वर कृपा करे, अगर मैंने भी कुछ बोला होता तो वे कहते, एक और गुस्से में ब्लैक मैन, इससे छुटकारा पाओ। ऐसी स्थिति में मैं एक और इनसान होता, जो कूड़े के ढेर में पड़ा मिलता।

डोपिंग जुर्माने से मिली रकम से बढ़ेगी इनामी राशि : सबेस्टियन

युगेन, (एजेंसी)। विश्व एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सबेस्टियन को ने कहा है कि रूस से डोपिंग जुर्माने के रूप में प्राप्त 20 लाख डॉलर की रकम का इस्तेमाल अगली दो विश्व चैंपियनशिप के लिए इनामी राशि को बढ़ाने में किया जाएगा। सबेस्टियन के अनुसार युगेन में 2022 और हंगरी के बुडापेस्ट में 2023 में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में प्रत्येक की इनामी राशि में 10 लाख डॉलर की राशि को बढ़ाया जाएगा।

प्रशंसकों को पसंद आया बड़ी मूछों और हिमाचली टोपी वाला अंदाज, शिमला में दिखे धोनी के कई रंग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भले ही धोनी का जन्म झारखंड में हुआ हो, लेकिन सभी जानते हैं कि उनका संबंध पहाड़ों से है। माही के पिता पान सिंह नौकरी के सिलसिले में उत्तराखंड से रांची जा बसे। तब से उनका पूरा परिवार वही का होकर रह गया। अब छुट्टियों में धोनी हिमाचल प्रदेश की सैर पर निकले हैं। हिमाचल प्रवास के दौरान उनके कई रंग देखने को मिल रहे हैं। वह बड़ी मूछें और हिमाचली टोपी में आकर्षक लग रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला पहुंचने पर धोनी ने मैहली स्थित हेवन होमस्टे में रात बिताई, इसके बाद धोनी शिमला के बाईपास रोड के कनलोग में ठहरे हुए हैं। पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी साथ हैं। माही के फैंस को जैसे ही यह पता चला कि उनका पसंदीदा क्रिकेटर शिमला की वादियों में घूम रहा है, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो उठे। धोनी ने भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान एक प्रशंसक ने उन्हें चार क्रिकेट बैट भेंट किए। धोनी ने खुद उन्हें जांचा और इसकी तारीफ की। ये बल्ले शिमला में ही बनाए गए हैं। धोनी की राजदुलारी नन्हीं बिटिया जीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कई तस्वीरें और वीडियोज अपलोड की गई है, जिसे हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। साक्षी ने भी अपने अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मौजूदा आशियाना देखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण की वजह से आईपीएल का 14वां सीजन स्थगित कर दिया गया था। इस बीच यूएई में इसके दोबारा शुरू होने की खबर है। 19 सितंबर से शुरू होने वाले दूसरे राउंड में धोनी यलो जर्सी में फिर दहाड़ मारते नजर आएंगे।

भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईसीसी से खफा, बोले-सभी एक चैंपियन चाहते थे

साउथैम्पटन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश के कारण पहले और चौथे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, जिससे खेल के रोमांच में कमी आई। खेल के हाल देख कर क्रकेट के फैंस परेशान हैं। साउथैम्पटन में बारिश के कारण अगर मैच का रिजल्ट नहीं निकलता है तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा, लेकिन इससे पूर्व क्रिकेटर खुश नहीं हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, यह फैंस के लिए बेहद दुखद है। मुझे आईसीसी के नियम सही नहीं लगे। सभी ने सब कुछ किया। आप एक चैंपियन चाहते थे। उन्होंने कहा कि इतना समय होने के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि 5 दिन में हर दिन के 90 ओवर के हिसाब से 450 ओवर फेंक जा सकेंगे। मैं आईसीसी से यही उम्मीद कर रहा था। सभी उत्साहित थे। एक दिन का रिजर्व डे भी रखा गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रिजर्व डे के बाद भी खेल पूरा हो सकेगा। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड ने कहा, दोनों टीमें जीत के लिए खेलती हैं। पिच पर गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ था। ऐसे में सिर्फ 3 से 4 दिन में हमें परिणाम देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मैं वीवीएस लक्ष्मण की बात से सहमत हूं कि मैं पूरे 450 ओवर और एक टॉप टीम का देखना चाहता हूं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगड़ ने कहा कि रिजल्ट निकलना जरूरी था। अगर टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 150-160 रन का लक्ष्य देती है तो चौथी पारी में उसके लिए यह आसान नहीं होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 23 जून को एक रिजर्व डे भी रखा गया है। इसका उपयोग तभी होगा जबकि पांच दिन में खेल के पूरे ओवर नहीं हो सकेंगे। अगर मैच ड्रॉ या टाई होता है तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। अब तक सिर्फ एक बार 2002 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में संयुक्त विजेता देखने को मिला था।

रनों के सूख से जूझ रहे पुजारा, लोगों ने कहा यह आखिरी मौका उनके पास

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा महज 8 रन ही बना सके। उन्होंने 36वीं गेंद पर अपना खाता खोला था, जिसके बाद से ही वह बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि अपनी धीमी शुरूआत को भी वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। पुजारा के इस प्रदर्शन के बाद से कहा जा रहा है कि उनका करियर खत्म होने के कगार पर है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पुजारा ने 85 मैचों की 142 पारी में 6 हजार 244 रन बनाए। उनकी सबसे बड़ी टेस्ट पारी नाबाद 206 रन की रही। पुजारा के नाम 18 टेस्ट शतक और 29 टेस्ट अर्धशतक है। मगर अब उनके सामने करियर को लंबा खींचने के लिए इंग्लैंड दौरे पर कुछ यादगार पारी खेलने की चुनौती खड़ी हो गई है। इंग्लैंड दौरे को उनके करियर का आखिरी मौका माना जा रहा है।

पुजारा पिछले काफी समय से रनों के सूखे से जूझ रहे हैं। अगस्त 2019 से उन्होंने 17 टेस्ट मैचों में 29.21 की औसत से महज 818 रन ही बनाए। इस दौरान वह एक भी शतक नहीं लगा पाए और 28 पारियों में सिर्फ 9 बार ही 50 रन तक पहुंचे। वहीं इंग्लैंड में पुजारा ने 9 टेस्ट मैचों में 29.41 की औसत से 500 रन बनाए। फाइनल में 36वीं गेंद पर खाता खोलने के बाद पुजारा ने दो चौके लगाए और इसके बाद कई गेंद डॉट खेली और फिर बोल्ट के शिकार हुए। इस दौरान वह स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके।

टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर का कहना है कि पुजारा को अपनी शुरूआत को बड़े स्कोर में बदलने की जरूरत है। इस फाइनल से पहले पुजारा का इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन देखने पर उन्होंने चार मैचों की 6 पारियों में 73, 15, 21, 7 , 0 और 17 रन बनाए है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की 8 पारियों में 43, 0, 17,3, 50, 77, 25, 56 रन बनाए थे।

एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स के जोहान क्रूफ एरिना में नीदरलैंड और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप ग्रुप सी मैच के दौरान नॉर्थ मैसेडोनिया के गोरान पांडव।